



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244885  
CG-DL-E-01042023-244885

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]  
No. 202]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 2023/चैत्र 11, 1945  
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 2023/CHAITRA 11, 1945

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

सं. 21/2023 - सीमा-शुल्क

**सा.का.नि. 254(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.03 के संदर्भ में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी एक वैध अग्रिम प्राधिकरण के सापेक्ष भारत में आयातित सामग्रियों को (इसके बाद उक्त प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) उस पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के पूरे शुल्क से छूट देता है जो निर्दिष्ट है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में और धारा 3 की उप-धाराओं (1), (3) और (5) के तहत उस पर लगाए जाने वाले कुल अतिरिक्त शुल्क से, उस पर लगने वाला एकीकृत कर धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत, धारा 3 की उप-धारा (9) के तहत उस पर लगने वाले माल और सेवा कर मुआवजा उपकर, धारा 8बी के तहत लगाए जाने वाले सुरक्षा शुल्क, धारा 9 के तहत लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए के तहत शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरी तरह से छूट प्रदान करती है, अर्थात्: -

(i) कि डेबिट के लिए निकासी के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष उक्त प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया है;

(ii) कि उक्त प्राधिकरण वहन करता है, -

(क) उन मामलों में आयातक और सहायक निर्माता का नाम और पता जहां एक व्यापारी निर्यातक को कथित प्राधिकरण जारी किया गया है; और

(ख) शिपिंग बिल संख्या (संख्याएं) और तारीख (तारीखें) और विवरण, मात्रा और परिणामी उत्पाद के निर्यात का मूल्य उन मामलों में जहां निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद आयात होता है; या

(ग) विवरण और अन्य विनिर्देश जहां लागू होते हैं आयातित सामग्री और परिणामी उत्पाद के निर्यात का विवरण, मात्रा और मूल्य जहां निर्यात दायित्व की पूर्ति से पहले आयात होता है;

(iii) कि आयातित सामग्री विवरण और अन्य विशिष्टताओं के अनुरूप है जहां लागू हो, प्राधिकरण में उल्लिखित है और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार है और उसका मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है;

(iv) कि निर्यात दायित्व के पूर्ण रूप से निर्वहन से पहले किए गए आयात के संबंध में, आयातित सामग्री की निकासी के समय आयातक इस तरह की जमानत या सुरक्षा के साथ एक बांड निष्पादित करता है और इस तरह के रूप में और ऐसी राशि के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, मांग पर शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करता है, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, आयातित सामग्री पर, जिसके संबंध में शर्तों में निर्दिष्ट शर्तें हैं उक्त सामग्री की निकासी की तिथि से पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित इस अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(v) कि पूर्ण रूप से निर्यात दायित्व के निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, यदि नियम 18 (परिणामी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान की गई शुल्क में छूट) या नियम 19 के उप-नियम (2) के तहत सुविधा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 या सेनवैट क्रेडिट नियम, 2017 के तहत सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है, तो आयातक, आयातित सामग्रियों की निकासी के समय सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को बांड प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है, खुद को बाध्य करने के लिए, अपने कारखाने में या अपने सहायक निर्माता के कारखाने में शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आयातित सामग्री का उपयोग करने के लिए और क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से या एक निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से छह महीने के भीतर एक प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उक्त सामग्रियों की निकासी की तारीख से, कि आयातित सामग्रियों का उपयोग किया गया है;

बशर्ते कि यदि आयातक आयातित सामग्री पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, तो आयातित सामग्री को इस शर्त में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है और इस प्रकार भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क सेनवैट क्रेडिट नियम, 2017 के तहत सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

(vi) कि निर्यात दायित्व के पूर्ण रूप से निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, और यदि नियम 18 (परिणामी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान की गई शुल्क की छूट) या नियम 19 के उप-नियम (2) के तहत सुविधा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 या सेनवैट क्रेडिट नियम, 2017 के तहत सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है और आयातक इस आशय का प्रमाण सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करता है, तो शर्त (v) में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना आयातित सामग्री की निकासी की जा सकती है;

(vii) कि निर्यात दायित्व के पूर्ण रूप से निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, यदि संबंधित माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा निर्माता के लिए इस्तेमाल किए गए इनपुट और निर्यात किए गए माल की आपूर्ति पर ली गई है, तो आयातक, आयातित सामग्री की निकासी के समय, सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अपने कारखाने में या अपने सहायक निर्माता के कारखाने में आयातित सामग्री का उपयोग करने के लिए बाध्य करने के लिए एक बंधन प्रस्तुत करें। कर योग्य वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए (शून्य रेटेड या पूरी तरह से छूट वाली आपूर्ति के अलावा) और उक्त सामग्रियों की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कि आयातित सामग्री का उपयोग किया गया है;

बशर्ते कि यदि आयातक आयातित सामग्री पर कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत आयातित सामग्री पर लगने वाले एकीकृत कर और माल और सेवा कर मुआवजा उपकर का भुगतान करता है लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, तो इस तरह की आयातित सामग्री को इस शर्त में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है;

(viii) कि निर्यात दायित्व के पूर्ण रूप से निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, और यदि प्रासंगिक माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट पर नहीं ली गई है और आयातक सीमा शुल्क के उपायुक्त, या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो आयातित सामग्री को शर्त (vii) में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है;

(ix) कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों के माध्यम से या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 26/2023-सीमाशुल्क दिनांक 01-04-2023 में संलग्न तालिका 2 या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के तहत अधिसूचित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में उल्लिखित है:

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश या एक सार्वजनिक नोटिस और उसके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी अन्य बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है।;

(x) कि उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट निर्यात दायित्व (मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में) उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त हो जाता है, जो भारत में जो उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट हैं, परिणामी उत्पादों, निर्मित उत्पादों का निर्यात करके क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है:

बशर्ते कि एक अग्रिम मध्यवर्ती प्राधिकरण धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.05 (सी)(ii) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात दायित्व का निर्वहन करेगा;

आगे बशर्ते कि उक्त प्राधिकारों के लिए इसमें ऊपर निहित कुछ भी होने के बावजूद जहां उक्त सीमा शुल्क टैरिफ की धारा 3 की उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत एकीकृत कर और माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है। अधिनियम का लाभ उठाया गया है, निर्यात दायित्व भौतिक निर्यात द्वारा पूरा किया जाएगा या अधिसूचना संख्या 48/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 सा.का.नि. संख्या 1305(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित में निहित तालिका के क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित घरेलू आपूर्ति करके पूरा किया जाएगा;

(xi) कि आयातक निर्यात की पूर्ति के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए निर्यात दायित्व के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। दायित्व, या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि सीमा शुल्क के उक्त उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अनुमति दे सकते हैं;

(xii) उक्त प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उक्त सामग्री को स्थानांतरित या बेचा नहीं जाएगा:

बशर्ते कि उक्त सामग्री को प्रसंस्करण के लिए जॉब वर्कर को हस्तांतरित किया जा सकता है, संबंधित माल और सेवा कर प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन जॉब वर्क के लिए सामग्री के हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है;

(xiii) कि एक व्यापारी निर्यातक को जारी किए गए उक्त प्राधिकरण के संबंध में, इस अधिसूचना के संदर्भ में आयातक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी भी बांड को व्यापारी निर्यातक द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तें सहायक निर्माता खुद को संयुक्त रूप से और अलग-अलग पालन करने के लिए बाध्य करेंगे।

2. जहां सामग्री दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, उक्त सामग्री को विदेशी आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर वापस निर्यात किया जा सकता है या ऐसी विस्तारित अवधि छह महीने की अतिरिक्त अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त अनुमति दे सकते हैं:

बशर्ते कि पुनः निर्यात के समय सामग्री की पहचान सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त की संतुष्टि के लिए की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, जो सामग्री आयात की गई थी।

स्पष्टीकरण, - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(i) "शुल्क योग्य माल" का अर्थ उत्पाद शुल्क योग्य सामान है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 'शून्य' दर से प्रभाव्य नहीं है;

(ii) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है विदेश व्यापार नीति, 2023, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समय-समय पर संशोधित रूप में प्रकाशित की गई है;

(iii) "क्षेत्रीय प्राधिकरण" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक या उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है;

(iv) "निर्माण" का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 11.31 में दिया गया है;

(v) "सामग्री" का अर्थ है, -

(क) कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती, उपभोग्य सामग्रियों, उत्प्रेरक और भागों जो परिणामी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हैं;

(ख) अनिवार्य पुर्जों को प्राधिकरण के मूल्य के दस प्रतिशत की मूल्य सीमा के भीतर परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात किया जाना आवश्यक है;

(ग) परिणामी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक ईंधन;

(घ) परिणामी उत्पाद की पैकिंग के लिए आवश्यक पैकेजिंग सामग्री;

(vi) "विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ एक वैधानिक लेखा परीक्षक या एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या केंद्र/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के तहत आयातक के वित्तीय रिकॉर्ड को प्रमाणित करता है।

(vii) "कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति" का अर्थ माल की आपूर्ति है जो संबंधित वस्तु और सेवा कर कानून के तहत कर के लिए लगाया जाता है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

#### No. 21/2023 - Customs

**G.S.R. 254(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against a valid Advance Authorisation issued by the Regional Authority in terms of paragraph 4.03 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3, integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3, goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub-section (9) of section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B, countervailing duty leviable thereon under section 9 and anti-dumping duty leviable thereon under section 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(ii) that the said authorisation bears,-

(a) the name and address of the importer and the supporting manufacturer in cases where the said authorisation has been issued to a merchant exporter; and

(b) the shipping bill number(s) and date(s) and description, quantity and value of exports of the resultant product in cases where import takes place after fulfillment of export obligation; or

(c) the description and other specifications where applicable of the imported materials and the description, quantity

and value of exports of the resultant product in cases where import takes place before fulfillment of export obligation;

(iii) that the materials imported correspond to the description and other specifications where applicable mentioned in the authorisation and are in terms of para 4.12 of the Foreign Trade Policy and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation;

(iv) that in respect of imports made before the discharge of export obligation in full, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen per cent per annum from the date of clearance of the said materials;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, if facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 or of CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2017 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer or from a specified chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2017;

(vi) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 or of CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2017 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (v);

(vii) that in respect of imports made after the discharge of exports obligation in full, if facility of input tax credit under relevant Goods and Service Tax law on inputs used for manufacturer and supply of goods exported has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials, furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempt supplies) and to submit a certificate from a chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used;

Provided that if the importer pays integrated tax and the goods and services tax compensation cess leviable on the imported materials under sub-section (7) and sub-section (9) respectively of section 3 of the said Customs Tariff Act on the imported materials but for the exemption contained herein, then such imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition;

(viii) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility of input tax credit under relevant Goods and Service Tax law has not been availed on inputs used in the manufacture and supply of goods exported and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs, or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (vii);

(ix) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No. 26/2023-Customs dated 1<sup>st</sup> April, 2023 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(x) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorisation:

Provided that an Advance Intermediate authorisation holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to exporter in terms of paragraph 4.05(c)(ii) of the Foreign Trade Policy;

Provided further that notwithstanding anything contained hereinabove for the said authorisations where the exemption from integrated tax and the goods and service tax compensation cess leviable thereon under sub-section (7) and sub-section (9) of section 3 of the said Customs Tariff Act, has been availed, the export obligation shall be fulfilled by physical exports or by making domestic supplies mentioned at serial numbers 1,2 and 3 of the Table contained in notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18<sup>th</sup> October, 2017 published, *vide* number G.S.R 1305(E), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017;

(xi) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(xii) that the said authorisation shall not be transferred and the said materials shall not be transferred or sold:

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions specified in the relevant goods and services tax provisions permitting transfer of materials for job work;

(xiii) that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter, any bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the merchant exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification.

2. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said material or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

*Explanation*, - For the purposes of this notification, -

(I) "dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

(II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;

(III) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation under the said Act;

(IV) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 11.31 of the Foreign Trade Policy;

(V) "Materials" means,-

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) mandatory spares within a value limit of ten per cent of the value of the authorisation which are required to be exported along with the resultant product;

(c) fuel required for manufacture of resultant product;

(d) packaging materials required for packing of resultant product;

(VI) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Central/State Goods and Services Tax Act.

(VII) "Supply of taxable goods" means a supply of goods which is leviable to tax under relevant Goods and Services Tax law.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.



**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

**सं. 22/2023 - सीमा-शुल्क**

**सा.का.नि. 255(अ).—** केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत में आयात किए जाने पर अंतिम माल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की पहली अनुसूची के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के पूरे शुल्क से छूट दी गई है। और धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, धारा 8ख के तहत लगाए जाने वाले सुरक्षा शुल्क, धारा 9 के तहत लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के तहत उस पर लगाया जा सकता है, इस अधिसूचना के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: -

(i) कि उक्त सामग्रियों के आयात की अनुमति देने वाली विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.05(ग)(iii) के संदर्भ में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आयातक को दिए गए निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार प्रदान किया गया है (बाद में उक्त प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित);

(ii) कि डेबिट के लिए निकासी के समय उक्त प्राधिकार सीमा शुल्क को उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है;

(iii) उक्त प्राधिकरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्दिष्ट करने वाले पृष्ठांकन शामिल हैं, -

(क) उक्त प्राधिकरण के तहत आयात की जाने वाली सामग्री का ब्यौरा, मात्रा और मूल्य; और

(ख) आयातित सामग्री से या उसके साथ निर्मित होने वाले अंतिम माल का ब्यौरा और मात्रा:

बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12(i) और 4.12(ii) में विनिर्दिष्ट इनपुट के संबंध में, उक्त प्राधिकरण में आयात की जाने वाली सामग्री क्रमशः विशिष्ट नाम या ब्यौरों या मात्रा की होगी, जैसा कि अंतिम वस्तुओं के निर्माण में आपूर्ति सामग्री प्रयोग की गई है। प्राधिकरण धारक इन विवरणों को एआरई-3 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रमाणित चालान जैसे दस्तावेजों पर घोषित करेगा;

(iv) कि निर्यात दायित्व के निर्वहन से पहले किए गए आयात के संबंध में, आयातित सामग्री की निकासी के समय आयातक इस तरह की जमानत या सुरक्षा के साथ एक बांड निष्पादित करता है, इस तरह के रूप में और इस तरह की राशि के लिए सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, मांग पर शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करता है, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, उस आयातित सामग्री पर जिसके संबंध में इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का उक्त सामग्रियों की निकासी की तारीख से पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अनुपालन नहीं किया जाता है;

(v) कि निर्यात दायित्व के निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 18 या नियम 19 के उप-नियम (2) या सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 के तहत सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2017 की सुविधा का उपयोग किया गया है, तो आयातक, आयातित सामग्री की निकासी के समय सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अपने कारखाने में आयातित सामग्री का उपयोग करने के लिए बाध्य करेगा या शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए अपने सहायक निर्माता के कारखाने में और उक्त सामग्रियों की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या एक विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कि आयातित सामग्री इसलिए इस्तेमाल किया कि:

यह प्रावधान करता है कि यदि आयातक आयातित सामग्री पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, तो आयातित सामग्री को इस शर्त पर विनिर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है और इस प्रकार भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क का लाभ उठाने के लिए पात्र सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2017 के तहत सेनवैट क्रेडिट होगा।

(vi) कि निर्यात दायित्व के निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, और यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 18 या नियम 19 के उप-नियम 2 या सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2017 के तहत सेनवैट क्रेडिट की सुविधा नहीं है और उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए आयातक इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो आयातित सामग्री को शर्त (v) में विनिर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है;

(vii) कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों के माध्यम से या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है जैसा कि अधिसूचना संख्या 26/2023- सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल, 2023 में संलग्न तालिका 2 में या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के तहत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र उल्लिखित है:

यह प्रावधान करता है कि सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश या एक सरकारी नोटिस और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी अन्य बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है। ;

(viii) कि उक्त प्राधिकरण (मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में) में विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त हो जाता है, जैसा कि क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा भारत में निर्मित अंतिम माल की आपूर्ति करके प्रदान किया जा सकता है जो उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट हैं;

(ix) कि आयातक, सीमा शुल्क के उक्त उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए अंतिम माल की आपूर्ति करने के दायित्व के निर्वहन करने की अवधि की समाप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करता है या दायित्व की पूर्ति के लिए अनुमति दी गई है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अनुमति दे सकते हैं;

(x) उक्त प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उक्त सामग्रियों को स्थानांतरित या क्रय नहीं किया जाएगा:

यह प्रावधान करता है कि उक्त सामग्री को प्रसंस्करण के लिए एक जॉब वर्कर को हस्तांतरित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित वस्तु और सेवा कर प्रावधानों में विनिर्दिष्ट उन शर्तों का पालन किया जाए जो जॉब वर्क के लिए सामग्री के हस्तांतरण की अनुमति देती है:

(xi) कि अंतिम माल के निर्माण के लिए आवश्यक घटक और पुर्जे, जिन्हें उत्पादन के कारखाने से हटाए जाने पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दी जाती है, प्रक्रियाओं और सीमाओं के अनुसार सीधे आयात के बंदरगाह से परियोजना स्थल तक ले जाया जा सकता है, यदि कोई हो, इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित इस शर्त के अधीन है कि ऐसे घटकों और भागों का विवरण और मात्रा और साइट का पता उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट किया गया है।

2. सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी-डॉपिंग ड्यूटी से छूट फाइनल गुड्स के लिए जरूरी सामग्री के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी, जो इस अधिसूचना के स्पष्टीकरण के खंड (III) के उप-खंड (क), (ग), (घ) और (i) के तहत आती हैं।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(I) "शुल्क योग्य माल" का अर्थ उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री से है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है और जो केंद्रीय



उत्पाद शुल्क की 'शून्य' दर से प्रभावित नहीं है;

(II) "निर्यात उन्मुख इकाइयों" का वही अर्थ है जो इसे विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.18 में दिया गया है;

(III) "अंतिम माल" का अर्थ है -

(क) वार्षिक आवश्यकता या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण योजना के लिए अग्रिम प्राधिकरण या अग्रिम प्राधिकरण के समक्ष माल की आपूर्ति;

(ख) निर्यात उन्मुख इकाइयों या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों या जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को माल की आपूर्ति;

(ग) निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामग्री प्राधिकरण के समक्ष पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति;

(घ) 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (घरेलू माल कंटेनर निर्माताओं) द्वारा समुद्री माल कंटेनरों की आपूर्ति, जहां ऐसे कंटेनर छह महीने की अवधि के भीतर भारत से निर्यात किए जाते हैं या ऐसी अतिरिक्त अवधि सीमा शुल्क के उपायुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो;

(ङ) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति या आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के तहत उन एजेंसियों या निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार अधिसूचित धन, जहां कानूनी समझौते सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन प्रदान करते हैं;

(च) उन एजेंसियों या निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार आईसीबी के तहत आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों या निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपकरणों (टर्नकी अनुबंधों की एकल जिम्मेदारी) की आपूर्ति और स्थापना, जहां विदेशों में निर्मित वस्तुओं के लिए डिलीवर ड्यूटी पेड (डीडीपी) कीमतों के आधार पर बोलियों को आमंत्रित और मूल्यांकित किया गया है;

(छ) किसी भी परियोजना या उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति, जिसके संबंध में वित्त मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित, शून्य पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देता है जिसे उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सीमा शुल्क और

जिनकी आपूर्ति आईसीबी प्रक्रिया के तहत की जाती है;

(ज) अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 की संख्या 598 की क्रम संख्या 31 में विनिर्दिष्ट मेगा विद्युत परियोजनाओं में से किसी की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, समय-समय पर संशोधित, यह प्रावधान करता है कि मेगा बिजली परियोजना उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट सीमा उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो। आपूर्ति आईसीबी प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए। यदि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आवश्यक मात्रा में बिजली का अनुबंध किया गया है या यदि परियोजना को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सम्मानित किया गया है, तो आईसीबी शर्त अनिवार्य नहीं होगी;

(झ) अधिसूचना संख्या 84/97-सीमा शुल्क दिनांक 11-11-1997 के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं या सरकारी उपयोग हेतु आपूर्ति के लिए;

(ञ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02 के खंड (च) में प्रदान किए गए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (एनसीबी) या आईसीबी के माध्यम से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति;

(IV) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ विदेश व्यापार नीति, 2023 है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समय-समय पर संशोधित रूप में प्रकाशित किया गया है।

(V) "सामग्री" का अर्थ है -

(क) कच्चा माल, घटकों, इंटरमीडिएटों, उपभोग्य सामग्रियों, उत्प्रेरक और भाग जो अंतिम माल के निर्माण के लिए आवश्यक हैं;

(ख) अनिवार्य पुर्जों को प्राधिकरण के मूल्य के दस प्रतिशत की मूल्य सीमा के भीतर अंतिम माल के साथ निर्यात किया जाना आवश्यक है;

(ग) अंतिम माल के निर्माण के लिए आवश्यक ईंधन;

(घ) अंतिम माल की पैकिंग के लिए आवश्यक पैकेजिंग सामग्री;

(VI) "क्षेत्रीय प्राधिकरण" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक या उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है; और

(VII) "विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ एक वैधानिक लेखा परीक्षक या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या केंद्र/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के तहत आयातक के वित्तीय रिकॉर्ड को प्रमाणित करता है।

(VIII) "कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति" का अर्थ माल की आपूर्ति से है जो संबंधित वस्तु एवं सेवा कर कानून के तहत कर के दायरे में है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

#### No. 22/2023 - Customs

**G.S.R. 255(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials required for the manufacture of the final goods when imported into India, from whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as Customs Tariff Act) and from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B, countervailing duty leviable thereon under section 9 and anti-dumping duty leviable thereon under section 9A of the said Customs Tariff Act, except specified in para 2 to this notification, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the importer has been granted Advance Authorisation for deemed export by the Regional Authority in terms of paragraph 4.05(c)(iii) of the Foreign Trade Policy permitting import of the said materials (hereinafter referred to as the said authorisation);

(ii) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit; (iii) that the said authorisation contains endorsements specifying, *inter alia* :-

(a) the description, quantity and value of materials allowed to be imported under the said authorisation; and

(b) the description and quantity of final goods to be manufactured out of, or with, the imported materials:

Provided that in respect of inputs referred in paragraphs 4.12(i) and 4.12(ii) of the Foreign Trade Policy, the material permitted to be imported in the said authorisation shall be of the specific name or description or quantity, respectively, as the material used in the manufacture of the final goods supplied. The said authorisation holder shall declare these particulars on the documents like ARE-3 and Central Excise Certified Invoice;

(iv) that in respect of imports made before the discharge of export obligation, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security, in such form and for such sum as may be

specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen per cent per annum from the date of clearance of the said materials;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, if facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 or of the CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2017 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer or from a specified chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2017;

(vi) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, and if facility under rule 18 or sub-rule 2 of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 or of the CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2017 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (v);

(vii) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No. 26/ 2023-Customs dated 1<sup>st</sup> April, 2023 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(viii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by supplying final goods manufactured in India which are specified in the said authorisation;

(ix) that the importer produces evidence of having discharged obligation to supply final goods to the satisfaction of the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days from the expiry of the period allowed for fulfillment of obligation or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(x) that the said authorisation shall not be transferred and the said materials shall not be transferred or sold:

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions specified in the relevant goods and services tax provisions permitting transfer of materials for job work:

(xi) that components and parts, required for manufacture of final goods which are wholly exempted from payment of excise duty when removed from the factory of production, may be taken directly from the port of import to the project site as per the procedures and limitations, if any, laid down by the Board in this regard subject to the condition that description and quantity of such components and parts and the address of the site have been specified in the said authorisation.

2. The exemption from safeguard duty, transitional product specific safeguard duty, countervailing duty and anti-dumping duty shall not be available in respect of material required for final goods which are covered under sub-clauses (a), (c), (d) and (i) of clause (III) of the Explanation to this notification.

*Explanation.* - For the purposes of this notification, -

(I) "dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

(II) "Export Oriented Units" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.18 of the Foreign Trade Policy;

(III) "Final goods" means -

(a) supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation Scheme;

(b) supply of goods to Export Oriented Units or Software Technology Parks or Electronic Hardware Technology Parks or Biotechnology Parks;

(c) supply of capital goods against Export Promotion Capital Goods Authorisation;

(d) supply of marine freight containers by 100% Export Oriented Units (domestic freight container manufacturers) where such containers are exported out of India within a period of six months or such further period as may be permitted by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;

(e) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or funds as notified by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with the procedures of those agencies or funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;

(f) supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or funds as notified by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under ICB in accordance with the procedures of those agencies or funds, where bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(g) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by notification No. 50/2017- Customs dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, as amended from time to time, permits import of such goods at zero customs duty subject to conditions specified in the said notification and the supply is made under ICB procedure;

(h) supply of goods required for setting up of any of the mega power projects specified in the list 31 at Sl. No. 598 of notification No. 50/2017-Customs dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, as amended from time to time, provided the mega power project conforms to the threshold generation capacity specified in the said Notification. The supply should be made under ICB procedure. The ICB condition shall not be mandatory if the requisite quantum of power has been tied up through tariff based competitive bidding or if the project has been awarded through tariff based competitive bidding;

(i) for supply for official use or to the projects funded by UN or International Organisation in terms of Notification No. 84/97-Customs dated the 11<sup>th</sup> November, 1997;

(j) Supply of goods to nuclear power projects through National Competitive Bidding (NCB) or through International Competitive Bidding (ICB) as provided in clause(g) of para 7.02 of Foreign Trade Policy;

(IV) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;

(V) "Materials" means -

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of final goods;

(b) mandatory spares within a value limit of ten per cent of the value of the authorisation which are required to be exported along with the final goods;

(c) fuel required for manufacture of final goods;

(d) packaging materials required for packing of final goods;

(VI) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation under the said Act; and

(VII) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Central/State Goods and Services Tax Act.

(VIII) "Supply of taxable goods" means a supply of goods which is leviable to tax under relevant Goods and Services Tax law.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

**संख्या 23/2023 - सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 256(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है करते हैं, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.07 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के साथ वार्षिक आवश्यकता के लिए एक वैध अग्रिम प्राधिकरण (इसके बाद उक्त प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) के सापेक्ष भारत में आयातित सामग्री को छूट देता है। उस पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क का शुल्क जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (बाद में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है और उप-धाराओं (1) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से), (3) और (5) धारा 3, धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत लगने वाले एकीकृत कर, माल और सेवा कर मुआवजा उपकर धारा 3 की उप-धारा (9) के तहत लगाए जाने योग्य, धारा 8बी के तहत लगाए जाने वाले सुरक्षा शुल्क, धारा 9 के तहत लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए के तहत लगाए जाने वाले एंटी-डंपिंग शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरी तरह से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

(i) कि उक्त प्राधिकरण को आयात की मात्रा और मूल्य के डेबिट के लिए मंजूरी के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

(ii) कि उक्त प्राधिकरण निर्धारित मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (सिओन) के संबंध में जारी किया गया है और इसमें, -

(क) उन मामलों में आयातक और सहायक निर्माता का नाम और पता जहां एक व्यापारी निर्यातक को प्राधिकरण जारी किया गया है; और

(ख) शिपिंग बिल संख्या (संख्याएं) और तारीख (तारीखें) और विवरण, मात्रा और परिणामी उत्पाद के निर्यात का मूल्य उन मामलों में जहां निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद आयात होता है; या

(ग) विवरण, लागत बीमा भाड़ा मूल्य और आयातित सामग्री के अन्य विनिर्देशों और विवरण, मात्रा और फ्री ऑन बोर्ड मूल्य प्रक्रिया पुस्तक में निर्दिष्ट एक निर्यात उत्पाद समूह के तहत कवर किया गया है, ऐसे मामलों में जहां निर्यात दायित्व की पूर्ति से पहले आयात होता है:

बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12(i) और 4.12(ii) में निर्दिष्ट इनपुट के संबंध में उक्त प्राधिकरण में आयात की जाने वाली सामग्री क्रमशः विशिष्ट नाम या विवरण या मात्रा की होगी, जैसा कि सामग्री परिणामी उत्पाद के निर्यात में उपयोग किया जाता है। निर्यातक इन विवरणों को शिपिंग बिल या निर्यात बिल में घोषित करेगा:

बशर्ते आगे कि विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.44 (बी) में निर्दिष्ट इनपुट के संबंध में, तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशों को आयात के समय घोषित किया जाएगा और उक्त प्राधिकरण में अनुमत सामग्री परिणामी उत्पाद के निर्यात में उपयोग की जाने वाली सामग्री (या उपयोग की जाने वाली) के समान तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशिष्टताओं का होना चाहिए:

बशर्ते यह भी कि निर्यातक शिपिंग बिल/निर्यात के बिल में परिणामी उत्पाद के निर्यात में प्रयुक्त सामग्री की तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशों के संबंध में घोषणा करेगा;

(iii) कि निर्यात दायित्व के पूरा किए जाने के पहले किए जाए वाले आयात के मामले में, आयातकर्ता आयातित सामग्री के क्लियरेंस के समय ऐसी स्योरिटी या सिक्योरिटी के साथ और ऐसे प्रारूप में या ऐसी राशि का, जो कि उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क निर्धारित करे, एक ब्रांड निष्पादित करके अपने को इस बार के लिए बचनबद्ध करता हो कि वह यदि इसमें निहित छूट नहीं दी जाती है तो वह मांगे किए जाने पर उस राशि के बराबर का भुगतान कर देगा जो कि ऐसी सामग्री पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर हो और यदि इस अधिसूचना में निहित शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वह उक्त सामग्री के क्लियरेंस की तारीख से 15% वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा।

(iv) कि निर्यात दायित्व के निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, यदि सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 के तहत सेनवेट क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाया गया है, तो आयातक आयातित सामग्री की निकासी के समय एक बांड प्रस्तुत करेगा। सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अपने कारखाने में या अपने सहायक

निर्माता के कारखाने में शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आयातित सामग्री का उपयोग करने और क्षेत्राधिकार से एक प्रमाण पत्र जमा करने के लिए खुद को बाध्य कर सकता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से उक्त सामग्रियों की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर, कि आयातित सामग्रियों का उपयोग किया गया है:

बशर्ते कि यदि आयातक आयातित सामग्री पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, तो आयातित सामग्री को इस शर्त में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है और इस प्रकार भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क का लाभ सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 के तहत सेनवेट क्रेडिट उठाने के लिए पात्र होगा।

(v) कि पूर्ण रूप से निर्यात दायित्व के निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, और यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 18 या नियम 19 के उप-नियम (2) या सेनवेट क्रेडिट नियमों के तहत सेनवेट क्रेडिट के तहत सुविधा है, 2017 का लाभ नहीं उठाया गया है और आयातक उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो आयातित सामग्री को शर्त (iv) में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है।);

(vi) कि निर्यात दायित्व के पूर्ण रूप से निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, यदि निर्यात किए गए माल के निर्माण और आपूर्ति के लिए उपयोग किए गए इनपुट पर प्रासंगिक माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाया गया है, तो आयातक, आयातित सामग्री की निकासी के समय, सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अपने कारखाने में या अपने सहायक निर्माता के कारखाने में आयातित सामग्री का उपयोग करने के लिए बाध्य करने के लिए एक बंधन प्रस्तुत करें। कर योग्य वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए (शून्य रेटेड या पूरी तरह से छूट वाली आपूर्ति के अलावा) और उक्त सामग्रियों की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कि आयातित सामग्री का उपयोग किया गया है;

बशर्ते कि यदि आयातक एकीकृत कर और वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा उपकर का भुगतान करता है कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की क्रमशः उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत आयातित सामग्रियों पर लगाया जाता है, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, तो ऐसी आयातित सामग्रियों को एक निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना साफ किया जा सकता है;

(vii) कि निर्यात दायित्व के पूर्ण रूप से निर्वहन के बाद किए गए आयात के संबंध में, और यदि प्रासंगिक माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट पर नहीं ली गई है और आयातक सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो आयातित सामग्री को शर्त (vi) में निर्दिष्ट बांड प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी जा सकती है;

(viii) कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है जैसा कि अधिसूचना संख्या 26 / 2023-सीमा शुल्क दिनांक 01-04-2023 से जुड़ी तालिका 2 में उल्लिखित है या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के तहत अधिसूचित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र;

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश या एक सार्वजनिक नोटिस और उसके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी अन्य बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है। ;

(ix) कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.36 के तहत स्थापित निजी बंधुआ गोदामों से आयातित सामग्रियों की सोर्सिंग की अनुमति होगी;

(x) कि उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट निर्यात दायित्व (मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में) उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त हो जाता है, जो परिणामी उत्पादों, निर्मित उत्पादों का निर्यात करके क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है। भारत में जो उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट हैं और जिसके संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 18 या नियम 19 के उप-नियम (2) के तहत सुविधा या प्रासंगिक माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए उपयोग किए गए इनपुट पर निर्यातित माल के निर्माण और आपूर्ति का लाभ नहीं उठाया गया है :

बशर्ते कि एक अग्रिम मध्यवर्ती प्राधिकरण धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.05(c)(ii) के अनुसार निर्यातक



को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात दायित्व का निर्वहन करेगा:

बशर्ते कि उक्त प्राधिकारों के लिए इसमें ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद जहां कथित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत उपकर योग्य एकीकृत कर और माल और सेवा कर मुआवजे से छूट दी गई हो।, का लाभ उठाया गया है, निर्यात दायित्व भौतिक निर्यात द्वारा पूरा किया जाएगा या अधिसूचना संख्या 48/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित तालिका के क्रम संख्या 1,2 और 3 में उल्लिखित घरेलू आपूर्ति करके पूरा किया जाएगा। संख्या 1305(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017;

(xi) कि आयातक निर्यात की पूर्ति के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए निर्यात दायित्व के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। दायित्व, या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि सीमा शुल्क के उक्त उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अनुमति दे सकते हैं;

(xii) कि निर्यात दायित्व के निर्वहन या ऐसी सामग्रियों की पुनःपूर्ति के अलावा किसी भी तरह से छूट वाली सामग्री का निपटान या उपयोग नहीं किया जाएगा और इस तरह से भरी गई सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि उक्त सामग्री को प्रसंस्करण के लिए एक जॉब वर्कर को हस्तांतरित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित माल और सेवा कर प्रावधानों में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए जो जॉब वर्क के लिए सामग्री के हस्तांतरण की अनुमति देता है:

(xiii) निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक को जारी किए गए उक्त प्राधिकरण के संबंध में, इस अधिसूचना के अनुसार आयातक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी भी बांड को निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा जैसा भी मामला हो और सहायक निर्माता इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए खुद को संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्य करता है;

(xiv) कि आयातित सामग्री के संबंध में सुरक्षा शुल्क, संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क और एंटी-डॉपिंग शुल्क से छूट उपलब्ध नहीं होगी-

(क) वार्षिक आवश्यकता या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के लिए अग्रिम प्राधिकरण या अग्रिम प्राधिकरण के सापेक्ष माल की आपूर्ति के लिए ;

(ख) निर्यातोन्मुख इकाई या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क को माल की आपूर्ति के लिए;

(ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) प्राधिकरण के खिलाफ माल की आपूर्ति के लिए;

(घ) 100% एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट (घरेलू फ्रेट कंटेनर-निर्माताओं) द्वारा समुद्री माल कंटेनरों की आपूर्ति के लिए, जहां उक्त कंटेनरों को 6 महीने के भीतर भारत से बाहर निर्यात किया जाता है या सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई ऐसी अतिरिक्त अवधि, के रूप में मामला हो सकता है; और

(ङ) अधिसूचना संख्या 84/97-सीमा शुल्क दिनांक 11-11-1997 के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं या आधिकारिक उपयोग के लिए आपूर्ति के लिए।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(I) "शुल्क योग्य माल" का अर्थ उत्पाद शुल्क योग्य सामान है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 'शून्य' दर से प्रभावित नहीं है;

(II) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ विदेश व्यापार नीति, 2023 है, जिसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 01/2023, दिनांक 31 मार्च 2023 को जारी किया गया है ;

(III) "प्रक्रियाओं की पुस्तिका" का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023, दिनांक दिनांक 31 मार्च 2023 को जारी किया गया है ;

(IV) "निर्माण" का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 11.31 में दिया गया है;

(V) "सामग्री" का अर्थ है

(ए) कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती, उपभोग्य सामग्रियों, उत्प्रेरक और भागों जो परिणामी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हैं;

(बी) अनिवार्य पुर्जों को प्राधिकरण के मूल्य के दस प्रतिशत की मूल्य सीमा के भीतर परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात किया जाना आवश्यक है;

(सी) परिणामी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक ईंधन;

(डी) परिणामी उत्पाद की पैकिंग के लिए आवश्यक पैकेजिंग सामग्री;

(VI) "क्षेत्रीय प्राधिकरण" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक या उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है;

(VII) "विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ एक वैधानिक लेखा परीक्षक या एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या बिक्री कर या के तहत आयातक के वित्तीय रिकॉर्ड को प्रमाणित करता है। राज्य सरकार का मूल्य वर्धित कर अधिनियम।

(VIII) "कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति" का अर्थ माल की आपूर्ति से है जो संबंधित वस्तु एवं सेवा कर कानून के तहत कर के दायरे में है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

#### No. 23/2023 - Customs

**G.S.R. 256(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India, against a valid Advance Authorisation for Annual Requirement (hereinafter referred to as the said Authorisation) with actual user condition issued by the Regional Authority in terms of Paragraph 4.07 of the Foreign Trade Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as Customs Tariff Act) and [from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3, integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3, the goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub-section (9) of section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B, countervailing duty leviable thereon under section 9 and anti-dumping duty leviable thereon under section 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the quantity and value of imports;

(ii) that the said authorisation is issued with respect to Standard Input Output Norms (SION) fixed and bears,-

(a) the name and address of the importer and the supporting manufacturer in cases where the said authorisation has been issued to a merchant exporter; and

(b) the shipping bill number(s) and date(s) and description, quantity and value of exports of the resultant product in cases where import takes place after fulfillment of export obligation; or

(c) the description, Cost Insurance Freight value and other specifications of the imported materials and the description, quantity and Free on Board value of exports of the resultant product covered under an export product group specified in the Hand Book of Procedures, in such cases where import takes place before fulfillment of export obligation:

Provided that in respect of inputs referred in paragraphs 4.12(i) and 4.12(ii) of the Foreign Trade Policy, the material permitted to be imported in the said authorisation shall be of the specific name or description or quantity, respectively, as the material used in the export of the resultant product. The exporter shall declare these particulars in the shipping bill or bill of export:

Provided further that in respect of the inputs specified in paragraph 4.44 (b) of the Hand Book of Procedures of the Foreign Trade Policy, the technical characteristics, quality and specifications shall be declared at the time of

import and the material permitted in the said authorisation shall be of the same technical characteristics, quality and specifications as the materials used (or to be used) in the export of the resultant product:

Provided also that the exporter shall give declaration with regard to the technical characteristics, quality and specifications of materials used in the export of resultant product, in the shipping bill/ bill of export;

(iii) that in respect of imports made before the discharge of export obligation, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials;

(iv) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, if facility of Cenvat Credit under Cenvat Credit Rules, 2017 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer or from a specified chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing Cenvat Credit under the Cenvat Credit Rules, 2017;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 or of Cenvat credit under Cenvat Credit Rules, 2017 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (iv);

(vi) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, if facility of input tax credit under relevant Goods and Services Tax law on inputs used for manufacture and supply of goods exported has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials, furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempt supplies) and to submit a certificate from a chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used;

Provided that if the importer pays integrated tax and the goods and services tax compensation cess leviable on the imported materials under sub-section (7) and sub-section (9) respectively of section 3 of the said Customs Tariff Act on the imported materials but for the exemption contained herein, then such imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition;

(vii) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility of input tax credit under relevant Goods and Services Tax law has not been availed on inputs used in the manufacture and supply of goods exported and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (vi);

(viii) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to Notification No. 26/2023-Customs dated 1<sup>st</sup> April, 2023 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(ix) that sourcing of the imported materials from Private Bonded Warehouses set up under paragraph 2.36 of the Foreign Trade Policy would be allowed;

(x) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorisation and in respect of which facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 has not been availed:

Provided that an Advance Intermediate authorisation holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to exporter in terms of paragraph 4.05(c)(ii) of the Foreign Trade Policy;

Provided further that notwithstanding anything contained hereinabove for the said authorisations where the exemption from integrated tax and the goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub-section (7) and sub-section (9) of section 3 of the said Customs Tariff Act, has been availed, the export obligation shall be fulfilled by physical exports or by making domestic supplies mentioned at serial numbers 1,2 and 3 of the Table contained in notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18<sup>th</sup> October, 2017 published vide number 1305(E), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017;

(xi) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(xii) that the exempt materials shall not be disposed of or utilized in any manner except for discharge of export obligation or for replenishment of such materials and the materials so replenished shall not be sold or transferred to any other person:

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions prescribed in the relevant goods and services tax provisions permitting transfer of materials for job work:

(xiii) that in relation to the said authorisation issued to a manufacturer exporter or merchant exporter, any bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the manufacturer exporter or merchant exporter as the case may be and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification;

(xiv) that the exemption from safeguard duty, transitional product specific safeguard duty, countervailing duty and anti-dumping duty shall not be available in respect of material imported-

(a) for supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation;

(b) for supply of goods to Export Oriented Unit or Software Technology Parks or Electronic Hardware Technology Parks or Biotechnology Parks;

(c) for supply of goods against Export Promotion Capital Good (EPCG) Authorisation;

(d) for supply of marine freight containers by 100% Export Oriented Unit (domestic freight container- manufacturers) where said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be; and

(e) for supply for official use or to the projects funded by UN or International Organisation in terms of Notification No. 84/97-Customs dated 11-11-1997.

*Explanation,-* For the purposes of this notification,-

(I) "dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

(II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;

(III) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedures, 2023 published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* public notice No. 01/2023, dated the 1<sup>st</sup> April, 2023;

(IV) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 11.31 of the Foreign Trade Policy;

(V) "Materials" means

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) mandatory spares within a value limit of ten per cent of the value of the authorisation which are required to be exported along with the resultant product;

(c) fuel required for manufacture of resultant product;

(d) packaging materials required for packing of resultant product;

(VI) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation under the said Act;

(VII) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Sales Tax or the Value Added Tax Act of the State Government.

(VIII) "Supply of taxable goods" means a supply of goods which is leviable to tax under relevant Goods and Services Tax law.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

### सं. 24/2023 - सीमा-शुल्क

**सा.का.नि. 257(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.18 (i) के साथ पठित पैरा 4.03 के संदर्भ में जारी किए गए एक अग्रिम प्राधिकरण के सापेक्ष भारत में आयातित सामग्रियों को प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.05 के अनुसार प्रतिबंधित मद के निर्यात के लिए छूट देता है (इसके बाद उक्त प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है) उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (51 से 1975) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है और धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत उस पर लगने वाला एकीकृत कर, धारा 3 की उप-धारा (9) के तहत लगने वाला माल और सेवा कर मुआवजा उपकर, धारा 8ख के तहत लगाए जाने वाले सुरक्षा शुल्क, धारा 9 के तहत लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाए जाने वाले एंटी-डंपिंग शुल्क, निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरी तरह से छूट प्रदान करती है, यथा: -

- (i) कि उक्त प्राधिकार-पत्र, जिसे कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, डेबिट के लिए निकासी के वक्त सीमा शुल्क के यथोचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;
- (ii) कि उक्त प्राधिकार-पत्र में आयातकर्ता का नाम और पता, आयातित माल का विवरण और उसकी अन्य विशिष्टताएं तथा परिणामी उत्पाद का विवरण और उसके निर्यात की मात्रा और मूल्य उल्लिखित होना चाहिए;
- (iii) कि आयातित माल, उक्त प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित विवरण तथा अन्य विशिष्टताओं, जहां लागू हो, के अनुरूप हों और उनका मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हो;
- (iv) कि निर्यात अधिसूचित निश्चित निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (एसआईओएन) के अंतर्गत या प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.06 में पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत पूर्व आयात शर्तों के अधीन किया जाता हो;
- (v) कि आयातकर्ता आयातित माल की निकासी के समय ऐसी जमानत या प्रतिभूति से युक्त एक बंधपत्र निष्पादित करता है जो कि उस रूप या उस राशि के रूप में होगी जिसको कि उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिसके द्वारा वह अपने को इस बात से प्रतिबद्ध करेगा कि उस आयातित माल, जिसके बारे में इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं हो पाता है, पर लगने वाले निहित छूट के बिना शुल्क के बराबर की राशि, उस पर 15% की वार्षिक की दर से उक्त माल के निकासी की तारीख से लगने वाले ब्याज के समेत, का भुगतान करेगा;

(vi) कि उक्त प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत कोई आयात या निर्यात दायित्व के पूरा करने के लिए किया जाने वाला उत्तरवर्ती निर्यात केवल उन्हीं समुद्री बंदरगाहों या विमानपत्तनों या इनलैंड कंटेनर डिपो या भू सीमा शुल्क स्टेशनों से किया जाता है जो निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट हैं:-

**सारणी**

क्र.सं.	ईडीआई युक्त पत्तन/आईसीडी/एलसीएस	अवस्थिति
1	समुद्री बंदरगाह	बेदी (रोजी-जामनगर सहित) चेन्नई, कोचीन, दाहेज, काकीनाडा, कांडला, कट्टुपल्ली (तमिलनाडु), कोलकाता, कृष्णापट्टनम, एन्नोर (तमिलनाडु), कराईकल (संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी), मगडाल्ला, मंगलौर, मर्मागोवा, मुंबई, मुंद्रा, नागापट्टिनम, न्हावाशेवा, पारादीप, पीपावाव, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम
2	विमानपत्तन	अहमदाबाद, बेंगलुरु, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम.
3	इनलैंड कंटेनर डिपो	आगरा, अहमदाबाद, मेलपक्कम गांव (अरक्कोणम तालुक, जिला वेल्लौर), बेंगलुरु, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेल्टीपाल्यम (तमिलनाडु), छेहाडता (अमृतसर), कोयंबटूर, दादरी, दौलताबाद (मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गहीं हरसार, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईरुगुर गांव (तमिलनाडु), इरुनगाट्टुकोट्टाई (एसआईपीसीओटी औद्योगिक पार्क, काट्टाराम्बक्कम गांव, श्रीपेरुम्बुदुर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु), जयपुर, जालंधर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मंडीदीप (जिला रायसेन), मरीपल्लेम गांव (जिला गुंटूर इडलापाडु तालुका में), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पाटली (गुडगांव), पीतमपुर (इंदौर), रायपुर, रेवाड़ी, तलेगांव (जिला पुणे), तिरुपुर, तूतीकोरिन, वडोदरा, वालुज (औरंगाबाद)
4	भू सीमा शुल्क स्टेशन	जोगबनी, पेट्रापोल, रक्सौल

(vii) कि निर्यात दायित्व, जैसा कि उक्त प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट है, को (मूल्य और मात्रा दोनों ही रूपों में) आयातित माल के निकासी की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे परिणामी उत्पादों (उक्त प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट) का निर्यात करके पूरा कर दिया जाता है-

(क) जिनका कि उक्त प्राधिकार-पत्र के एवज में आयातित माल का प्रयोग करते हुए भारत में विनिर्माण किया गया हो; और

(ख) जिनके बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 ( विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क में छूट) या नियम 19 के उप-नियम (2) के अंतर्गत सुविधाएं न ली गई हों; और

(viii) कि उक्त प्राधिकार-पत्र धारक निर्यात दायित्व को प्रतिपादित मूल्य संवर्धन के साथ पूरा करता है;

(ix) कि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.49 के प्रावधानों में निहित कोई बात उक्त प्राधिकार-पत्र के संबंध में लागू नहीं होगी;



(x) कि प्राधिकार-पत्र धारक निर्यात के समय इस आशय का वचनपत्र देता है कि परिणामी उत्पाद, जिसका कि उक्त प्राधिकार-पत्र के एवज में निर्यात किया जा रहा हो, जो कि अन्यथा निर्यात के लिए निषिद्ध है, का विनिर्माण उस सामग्री से किया गया है जिसका कि उक्त प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत पहले ही आयात किया गया हो तथा उक्त वचनपत्र में उक्त प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत किए गए आयात और निर्यात का ब्यौरा दिया गया हो;

(xi) कि उक्त प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और आयातित सामग्री वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगी और उसका किसी भी प्रयोजन या किसी भी उपाय से विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जाएगा यहां तक कि निर्माण कार्य के लिए भी नहीं;

(xii) कि आयातकर्ता निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिए उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति दें, या उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतुष्टि के लिए निर्यात दायित्व पूरा किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

2. जहां कि, उक्त माल दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो उक्त माल को इसकी क्लियरेंस की तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसी अवधि तक जैसा कि आयुक्त, सीमा शुल्क अनुमति दे जो कि निर्धारित अवधि से अधिकतम 30 दिन और अधिक हो सकती है, के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस निर्यात किया जा सकता है:

बशर्ते कि, उस समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हो कि वापस निर्यात किया जाने वाला माल वही है जिसका कि आयात किया गया था।

**स्पष्टीकरण**— इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, -

(I) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2023 से है जिसका प्रकाशन दिनांक 31 मार्च, 2023 को भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 01/2023 में समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(II) “प्रक्रिया पुस्तिका ” से अभिप्राय प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 से है जिसका प्रकाशन दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना सं. 01/2023, में समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(III) “विनिर्माण” का वही अभिप्राय है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 11.31 में दिया गया है।

(IV) “सामग्री” से अभिप्राय ऐसे कच्चे माल, उपभोग योग्य माल, ईंधन और पैकेजिंग सामग्री से है जिसकी जरूरत परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में होती है;

(V) “क्षेत्रीय प्राधिकारी” से अभिप्राय विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की जाती है या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी से भी है जिसको कि उसने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार-पत्र, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप समेत, जारी करने के लिए प्राधिकृत किया होता है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2023

**No. 24/2023 - Customs**

**G.S.R. 257(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against an Advance Authorisation issued in terms of paragraph 4.03 read with paragraph 4.18 (i) of the Foreign Trade Policy meant for export of a prohibited item in terms of paragraph 4.05 of the Handbook of Procedures (hereinafter referred to as the said authorization) from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as Customs Tariff Act) and from the whole of the additional duty, leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3, integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3, the goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub-section (9) of section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B, countervailing duty leviable thereon under section 9 and anti-dumping duty leviable thereon under section 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :-

(i) that the said authorisation, issued by the Regional Authority, is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(ii) that the said authorisation bears the name and address of the importer, the description and other specifications of the imported material and the description, quantity and value of exports of the resultant product;

(iii) that the imported material corresponds to the description and other specifications, where applicable, mentioned in the said authorisation and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation;

(iv) that the export is made subject to pre-import condition under notified Standard Input Output Norms (SION) or under prior fixation of norms in terms of Para 4.06 of Handbook of Procedures;

(v) that the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen per cent per annum from the date of clearance of the said materials;

(vi) that the imports under the said authorisation and the subsequent exports for fulfilling the export obligation are undertaken only through the seaports or airports or Inland Container Depots or Land Customs Stations which are specified in the Table below:-

**TABLE**

S. No.	EDI- enabled Port/ ICD/LCS	Located at
1.	Seaport	Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Kakinada, Kandla, Kattupalli (Tamil Nadu), Kolkata, Krishnapatnam, Ennore (Tamil Nadu), Karaikal (Union territory of Puducherry), Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Mumbai, Mundra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Tuticorin, Visakhapatnam
2.	Airport	Ahmedabad, Bengaluru, Calicut, Chennai, Cochin, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Trivandrum, Visakhapatnam
3.	Inland Container Depot	Agra, Ahmedabad, Melpakkam Village (Arakkonam Taluk, Vellore District), Bengaluru, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamil Nadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Daulatabad (Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Hyderabad, Irugur Village (Tamil Nadu), Irungattukottai (SIPCOT Industrial Park, Kattrambakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamil Nadu), Jaipur, Jalandhar, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Mandideep (District Raisen), Marripalem Village (in Edlapadu Taluk of District Guntur), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Patli (Gurgaon), Pitampur (Indore), Raipur, Rewari, Talegaon (District Pune), Tirupur, Tuticorin, Vadodara, Waluj (Aurangabad).

4.	Land Customs Station	Jogbani, Petrapole, Raxaul
----	----------------------	----------------------------

(vii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within ninety days from the date of clearance of imported materials by exporting the resultant product (specified in the said authorisation),-

(a) which is manufactured in India using the material imported against the said authorisation; and

(b) in respect of which the facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in manufacture) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 has not been availed; and

(viii) that the Authorisation Holder fulfills the export obligation, including the stipulated value addition;

(ix) that nothing contained in the provisions of Para 4.49 of Handbook of Procedures shall be applicable in relation to the said authorisation;

(x) that at the time of export the authorisation holder gives an undertaking to the effect that the resultant product, being exported against the said authorisation, which is otherwise prohibited for export, has been manufactured from the material already imported under the said authorisation and the said undertaking contains the details of the imports and exports made under the said authorisation;

(xi) that the said authorisation shall not be transferred and the imported material shall be subject to actual user condition and shall not be sold or transferred for any purpose, or by any means, including job work;

(xii) that the importer produces evidence of discharge of the export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow.

2. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within thirty days from the date of clearance of the said material or such extended period, not exceeding a further period of thirty days, as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

*Explanation, -* For the purpose of this notification, -

(I) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;

(II) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedures, 2023 published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* public notice No. 01/2023, dated the 1<sup>st</sup> April 2023;

(III) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 11.31 of the Foreign Trade Policy;

(IV) "Materials" means raw materials, consumables, fuel and packaging materials required for manufacturing of the resultant product;

(V) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

**सं. 25/2023 - सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 258(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है करते हैं, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.24 और 4.26 के संदर्भ में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध शुल्क मुक्त आयात

प्राधिकर पत्र के सापेक्ष भारत में आयातित सामग्री को (इसके बाद उक्त प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) पूरे सीमा शुल्क से छूट देता है। जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्: -

- (i) कि डेबिट के लिए निकासी के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष उक्त प्राधिकर पत्र प्रस्तुत किया गया है;
- (ii) कि मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) संख्या, विवरण, मात्रा और निर्यात किए गए परिणामी उत्पाद के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त और शिपिंग बिल नंबर (संख्या) और तारीख (तारीखें) उक्त प्राधिकरण पर पृष्ठांकित हैं:

बशर्ते कि उक्त एसआईओएन वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त निर्धारित नहीं करता है;

- (iii) कि जहां भी लागू हो, विवरण और अन्य विनिर्देश, आयातित सामग्रियों का मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकरण में उल्लिखित हैं और उनका मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हैं:

बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12(i) और 4.12(ii) में निर्दिष्ट इनपुट के संबंध में उक्त प्राधिकरण में आयात की जाने वाली सामग्री क्रमशः विशिष्ट नाम/विवरण या मात्रा की होगी, क्योंकि सामग्री परिणामी उत्पाद के निर्यात में उपयोग किया जाता है। निर्यातक शिपिंग बिल/निर्यात बिल में प्रयुक्त सामग्री के इन विवरणों की घोषणा करेगा:

बशर्ते आगे कि परिणामी उत्पादों के संबंध में विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.29 में निर्दिष्ट इनपुट की आवश्यकता होती है, उक्त प्राधिकर पत्र में अनुमत सामग्री उसी गुणवत्ता, तकनीकी विशेषताओं और विशिष्टताओं की होगी, जो उक्त परिणामी उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री की होती है। निर्यातक शिपिंग बिल या निर्यात बिल में प्रयुक्त सामग्री के इन विवरणों की घोषणा करेगा;

- (iv) उक्त प्राधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन हस्तांतरणीय होगा जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं;

- (v) कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों के माध्यम से या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है जैसा कि अधिसूचना संख्या 26/2023- सीमा शुल्क दिनांक 01-04-2023 के साथ संलग्न तालिका 2 में उल्लिखित है। या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के तहत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र:

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश या एक सार्वजनिक नोटिस और उसके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी अन्य बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है। ;

- (vi) उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट निर्यात (मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.28 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत में निर्मित परिणामी उत्पादों का निर्यात करके पूरा किया गया था, जो उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट हैं :

बशर्ते कि मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए एक प्राधिकरण के मामले में, विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.05 (सी) (ii) के संदर्भ में निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात दायित्व का निर्वहन किया जाएगा;

- (vii) कि आयातक सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए निर्यात दायित्व को पूरा करने का सबूत पेश करता है;

- (viii) कि किसी व्यापारी निर्यातक को जारी किए गए उक्त प्राधिकर पत्र के संबंध में, निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले सहायक निर्माता का नाम और पूरा डाक पता शिपिंग बिलों में घोषित किया गया है और उक्त प्राधिकरण में निर्दिष्ट किया गया है।

2. जहां सामग्री दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, उक्त सामग्री को विदेशी आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर वापस निर्यात किया जा सकता है या ऐसी विस्तारित अवधि छह महीने की अतिरिक्त अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त अनुमति दे सकते हैं:

बशर्ते कि पुनः निर्यात के समय, उपायुक्त सीमा शुल्क या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए सामग्री की पहचान की जाती है, जो सामग्री आयात की गई थी।

व्याख्या, - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

- (I) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ विदेश व्यापार नीति, 2023 है, जिसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रकाशित किया गया है;

(II) "विनिर्माण" का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 11.31 में दिया गया है;

(III) "सामग्री" का अर्थ है, -

(ए) कच्चे माल, घटकों, मध्यवर्ती, उपभोग्य सामग्रियों, उत्प्रेरक और भागों जो परिणामी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हैं;

(बी) परिणामी उत्पाद की पैकिंग के लिए आवश्यक पैकेजिंग सामग्री;

(IV) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक या उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

#### No. 25/2023 - Customs

**G.S.R. 258(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against a valid Duty Free Import Authorisation issued by the Regional Authority in terms of paragraphs 4.24 and 4.26 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), subject to the following conditions, namely :-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(ii) that Standard Input Output Norms (SION) number, description, quantity and Free on Board value of the resultant product exported and the shipping bill number(s) and date(s) are endorsed on the said authorisation:

Provided that the said SION does not prescribe the actual user condition;

(iii) that the description and other specifications wherever applicable, value and quantity of materials imported are mentioned in the said authorisation and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation:

Provided that in respect of inputs referred in paragraphs 4.12(i) and 4.12(ii) of the Foreign Trade Policy, the material permitted to be imported in the said authorisation shall be of the specific name or description or quantity, respectively, as the material used in the export of the resultant product. The exporter shall declare these particulars of materials used in the shipping bill/ bill of export:

Provided further that in respect of resultant products requiring inputs specified in paragraph 4.29 of the Foreign Trade Policy, the materials permitted in the said authorisation shall be of the same quality, technical characteristics and specifications as the materials used in the said resultant product. The exporter shall declare these particulars of materials used in the shipping bill or bill of export;

(iv) that the said authorisation shall be transferable subject to such conditions as may be specified;

(v) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No. 26/2023-Customs dated 1<sup>st</sup> April, 2023 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(vi) that the exports as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) were fulfilled within the period specified in paragraph 4.28 of the Foreign Trade Policy by exporting resultant products, manufactured in India, which are specified in the said authorisation:

Provided that in case of an authorisation for intermediate supply, the export obligation shall have been discharged by supplying the resultant products to the exporter in terms of paragraph 4.05(c)(ii) of the Foreign Trade Policy;

(vii) that the importer produces evidence of fulfillment of the export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;

(viii) that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter, the name and complete postal address of the supporting manufacturer who manufactured the export product is declared in the shipping bills and specified in the said authorization.

2. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said material or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export, the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

Explanation, - For the purposes of this notification,-

(I) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;

(II) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 11.31 of the Foreign Trade Policy;

(III) "Materials" means,-

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) packaging materials required for packing of resultant product;

(IV) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation under the said Act.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

सं. 26/2023 - सीमा शुल्क

**सा.का.नि. 259(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, एतश्मिन संलग्न सारणी 1 में विनिर्दिष्ट माल को निम्न से छूट प्रदान करती है,-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)(एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से; और

(ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धाराएँ (1), (3), और (5) के अंतर्गत लगाये जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से; जब आयातकर्ता द्वारा इसके लिए विशिष्ट रूप से दावा किया गया हो।

(iii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धाराएँ (7) और (9) के तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर और माल और सेवा कर मुआवजा उपकर।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट निम्न शर्तों के अधीन होगी, यथा:-

(1) आयातित माल विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के तहत जारी किये गये वैध प्राधिकार के दायरे में आता हो जिसके द्वारा शून्य सीमा शुल्क की दर पर ऐसे माल के आयात किये जाने की अनुमति दी गई हो.



(2) यह प्राधिकार पत्र उस आयात पत्तन में पंजीकृत हो जो कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट किया गया हो और वह माल जो कि एतश्मिन संलग्न सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है, उक्त प्राधिकार की वैधता के भीतर आयात किया गया हो और उक्त प्राधिकार को निकासी के समय उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष डेबिट (नामे) के लिए प्रस्तुत किया जाता हो:

बशर्ते कि अनुवर्ती प्रभार चार्ज के लिए उत्प्रेरक की अनुमति उस प्राधिकार-पत्र के तहत दी जाएगी जिसमें संयंत्र, मशीनरी या उपकरण और प्रारंभिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक का आयात किया गया है, उन मामलों को छोड़कर जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुवर्ती प्रभार के लिए उत्प्रेरक के लिए एक अलग प्राधिकार जारी करता है। प्रारंभिक शुल्क के लिए संयंत्र, मशीनरी या उपकरण और उत्प्रेरक पहले ही आयात किए जा चुके हैं।

(3) उक्त प्राधिकारी के अंतर्गत आयातित माल का निपटान अथवा बिक्री अथवा लीज अथवा अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर दिया जाता है।

(4) आयातक इस के रूप में और इस तरह की राशि के लिए और इस प्रकार की जमानत या सुरक्षा के साथ एक बांड निष्पादित करता है जैसा कि सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा इस अधिसूचना की सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बोर्ड पर निःशुल्क (एफओबी) आधार पर निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के छह गुना के बराबर, जैसा कि प्राधिकार-पत्र पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, या ऐसी उच्च राशि के लिए जो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा तय या समर्थन किया जा सकता है प्रक्रिया हैंड बुक का पैरा 5.15, प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख से छह साल की अवधि के भीतर, निम्नलिखित अनुपात में, अर्थात्:-

क्र.सं.	प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने की तिथि से अवधि	कुल निर्यात दायित्व का अनुपात
(1)	(2)	(3)
1.	पहले से चौथे वर्ष तक का ब्लॉक	50%
2.	पांचवे और छठे वर्ष का ब्लॉक	शेष-ईओ:

बशर्ते कि यदि सामान्य सेवा प्रदाता(सीएसपी) को प्राधिकार-पत्र जारी कर दिया गया है तो वह सीएसपी बैंक प्रत्याभूति के साथ एक बंधपत्र भरेगा और यह बैंक प्रत्याभूति परित्यक्त राजस्व के 100 प्रतिशत के समतुल्य होगी, और यह बैंक प्रत्याभूति सीएसपी द्वारा या किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा या दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से, सीएसपी के विकल्प पर, दी जाएगी:

बशर्ते आगे कि निर्यात दायित्व ऊपर निर्दिष्ट सामान्य निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत होगा, जब निम्नलिखित हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों, अर्थात्, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उसके पुर्जे या उपकरण, पवन ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उसके पुर्जे या उपकरण, एलईडी, विभिन्न प्रकार की एलईडी लाइट, वाष्प अवशोषण चिलर, अपशिष्ट ताप बॉयलर, अपशिष्ट ताप वसूली इकाइयां, अल्फायर हीट रीकवरी स्टीम जनरेटर, जल उपचार संयंत्र, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी)(हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी) और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा(PHEV)), सभी प्रकार के, वर्टिकल फार्मिंग उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल फिल्टर, और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात द्वारा पूरा किया जाता है:

बशर्ते यह भी कि अरुणांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम नागालैण्ड, सिक्किम त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में स्थित इकाइयों के लिए निर्यात दायित्व उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व का 25 प्रतिशत होगा:

बशर्ते यह भी कि ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र रखने वाली एक इकाई और दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के प्रावधानों के तहत भर्ती की गई है और जिनके संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा आईबीसी (IBC) 2016 की धारा 31 के तहत संकल्प योजना को मंजूरी दी गई है न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित या अंतिम रूप दी गई संकल्प योजना के अनुसार राहत, रियायतें और छूट की अनुमति दी जाएगी.

(5) यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धाराएँ (1), (3), (5), (7) और (9) खंड 3 के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट के लिए दावा नहीं करता है तो इस प्रकार इसके द्वारा भुगतान किये गये अतिरिक्त सीमा शुल्क को निर्यात दायित्व को निर्धारित करने के लिए बचाये गये निवल शुल्क की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा. बशर्ते कि भुगतान किये गये अतिरिक्त शुल्क का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया हो;

(6) आयातकर्ता, जिसमें सीएसपी भी शामिल है, प्राधिकार-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से प्रत्येक ब्लॉक की समामी से तीस दिन के भीतर, या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क अनुमति प्रदान करे, उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क के संतुष्टि हेतु ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिससे जाहिर हो कि निर्यात दायित्व पूरा हो गया है, और जहां किसी विशेष ब्लॉक के निर्यात दायित्व को पैरा 2 के उप-पैरा (4) के अनुसार पूरा नहीं किया जाता है, आयातकर्ता उक्त ब्लॉक की समामी से तीन महीने के भीतर इतनी राशि के बराबर सीमा शुल्क का, माल के निकासी की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के साथ, भुगतान करेगा जिसका उक्त माल पर लगाये जाने वाले शुल्क, जबकि निहित छूट नहीं ली गई से वह अनुपात हो जो कि निर्यात दायित्व के पूरा न किये जाने वाले हिस्से की कुल निर्यात दायित्व के साथ हो.

(7) जहां आयातकर्ता उक्त शर्त (4) में उल्लिखित निर्यात दायित्व के लिए विहित अवधि की आधी अवधि के भीतर निर्यात दायित्व (औसत निर्यात दायित्व के 100 प्रतिशत से अधिक एवं ऊपर) का 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक, जैसा कि शर्त (4) में निर्दिष्ट किया गया है पूरा करता है उस मामले में बकाया निर्यात दायित्व को समाप्त कर दिया जायेगा तथा यह माना जायेगा कि उसने अपनी निर्यात दायित्व पूरी कर ली है;

बशर्ते उपरोक्त शर्त (4) के परंतुक 2 और परंतुक 3 के अनुसार घटी हुई निर्यात बाध्यता का लाभ नहीं लिया गया हो.

(8) आयातित, एसेम्बलड या विनिर्मित पूंजीगत माल को आयात के बाद आयातकर्ता के कारखाने या उसके परिसर में संस्थापित और उपयोग किया जाएगा और वह आयात के पूरा होने की तारीख से छः माह के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त उपायुक्त (या सहायक आयुक्त), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा स्वतंत्र चार्टर्ड अभियंता से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाणपत्र उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत करता है कि उक्त पूंजीगत माल को आयातकर्ता के कारखाने या उसके परिसर में संस्थापित और उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है:

बशर्ते कि जिन मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी उक्त अवधि को आयात पूरा करने की तारीख से छः माह से अधिक के लिए बढ़ाता है तो, उपर्युक्त संपूर्ण अवधि को उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, द्वारा बढ़ाया जाएगा;

बशर्ते आगे कि एक आयातक (एक आयातक सहित जो एक सीएसपी है स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर के (प्रमाण पत्र का विकल्प चुनता है, प्रमाण पत्र की एक प्रति, इसके जारी होने पर, सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, जिसका आयातक के कारखाने या परिसर पर अधिकार क्षेत्र हो, को सूचना या रिकॉर्ड के रूप में भेजेगा,;

बशर्ते यह भी कि कलपुर्जों, के आयात के मामले में संस्थापन प्रमाणपत्र आयात की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि विनिर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक जिसके पास सहयोगी निर्माता हैं अथवा कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए संविदा फॉर्मों में प्रयोग किए जाने वाले सिंचाई उपस्करों के आयात के मामले में अथवा सेवा प्रदाता आयातक के मामले में पूंजीगत वस्तुएं ऐसे अन्य व्यक्ति के कारखाने या स्थान पर लगाई जा सकती हैं जिसका नाम और पता शर्त (1) में निर्दिष्ट प्राधिकार पर स्थापन के पहले से क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित है। यह तब भी लागू होगा जब क्षेत्रीय प्राधिकारी कारखाने या स्थान या व्यक्ति में बदलाव का पृष्ठांकन करता है। ऐसे अन्य व्यक्ति का नाम तथा पता शिपिंग बिल पर भी उल्लेखित किया जायेगा। यह सीएसपी पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि कृषि निर्यात जोन में अवस्थित कृषि इकाइयां अथवा कृषि विकास जोन के सेवा प्रदाता, क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को सूचित करते हुए कृषि निर्यात जोन के भीतर पूंजीगत वस्तुओं की आवाजाही, इस शर्त के अधीन कर सकता है की आयातक इस तरह की आवाजाही का सही रिकॉर्ड रखेगा।

(9) यह कि आयात और निर्यात संलग्न सारणी 2 में उल्लिखित समुद्री बंदरगाहों, विमानपत्तनों अथवा इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशनों अथवा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किया जाता है:

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त विशेष आदेश अथवा सार्वजनिक आदेश के माध्यम से और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की शर्तों के अध्याधीन अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(10) उपर्युक्त शर्त (4) में विहित किसी भी बात की परवाह न करते हुए, जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी ब्लॉक की ब्लॉकवार अवधि को बढ़ाये जाने अथवा निर्यात दायित्व की पूर्ति की समग्र अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाये जाने अथवा निर्यात दायित्व में कमी को नियमित करने, जो इस प्रकार के निर्यात दायित्व के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, के लिए आज्ञा देता है तो निर्यात दायित्व की उपर्युक्त ब्लॉकवार अवधि अथवा समग्र अवधि उपायुक्त सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, द्वारा बढ़ा दी जाएगी अथवा इसमें छूट दे दी जाएगी:

बशर्ते कि उपर्युक्त शर्त (4) के 4वें परंतुक में उल्लिखित इकाइयों के संबंध में निर्यात दायित्व की समग्र अवधि को बढ़ाये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. जहां कहीं सारणी 1 में विनिर्दिष्ट वस्तुएं सही नहीं पाई जाती अथवा प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो ये वस्तुएं निकासी की तिथि के तीन वर्ष के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को पुनःनिर्यात की जा सकती है:

बशर्ते कि पुनः निर्यात करने के समय इन वस्तुओं की उपायुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि अनुसार पहचान कर ली जाए कि ये वही वस्तुएं हैं जिनका आयात किया गया था;

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए-

(क) “पूंजीगत माल” का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 11.08 में दिया गया है;

(ख) “सामान्य सेवा प्रदाता” (सी एस पी) का अर्थ उस सेवा प्रदाता से है जिसे महानिदेशक विदेश व्यापार- मुख्यालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अथवा राज्य औद्योगिकी बुनियादी संरचना निगम द्वारा किसी उत्कृष्ट नगर या प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स (PM MITRA) द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता के रूप में नामित या प्रमाणित किया गया हो;

(ग) “निर्यात दायित्व”, -

(I) का अर्थ है आयातक पर इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल के उपयोग द्वारा उत्पादित उत्पादन के लिए सक्षम उत्पाद अथवा दी गई सेवा का भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात तथा यह निर्यात दायित्व, बढ़ाई गई

अवधि, यदि कोई हो, सहित समग्र निर्यात दायित्व अवधि के अंतर्गत उन्हीं उत्पादों या इसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आयातक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर, के अलावा होगी, तथा यह औसत उन्हीं उत्पादों तथा इसी तरह के उत्पादों के लिए विगत 3 वर्षों में निर्यात निष्पादन का अंकगणित औसत होगा:

बशर्ते कि हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों), कृषि, जलीय कृषि (मत्स्य पालन सहित), मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी, फूलों की खेती और बागवानी, पोल्ट्री, अंगूर की खेती, रेशम की खेती, कालीन, काँयर, जूट से संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में आयातक को निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि एकवाकल्चर (मत्स्य पालन सहित) से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक के लिए निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा बशर्ते कि फिशिंग ट्रालर्स, बोट, शिप एवं अन्य ऐसी मदों को छोड़कर माल के लिए ईपीसीजी प्राधिकार प्राप्त किया गया हो:

बशर्ते यह भी कि इस अधिसूचना के अंतर्गत औजारों को छोड़कर आयातित माल को उपर्युक्त क्षेत्रों द्वारा आयात की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी, उन मामलों में भी नहीं जहां निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया हो:

बशर्ते यह भी कि विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित देशों को किए गए निर्यात को निर्यात के औसत स्तर निर्धारित करने के लिए गिना नहीं जाएगा:

बशर्ते यह भी कि केवल ऐसे शिपिंग बिलों के द्वारा निर्यात को निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा जिन पर प्राधिकार संख्या और तिथि का उल्लेख होगा:

बशर्ते यह भी कि किसी सी एस पी को जारी प्राधिकार के मामले में, -

(i) इस स्पष्टीकरण में आयातकर्ता के संदर्भ में 'सीएसपी और ऐसे विशिष्ट उपयोगकर्ताओं का संदर्भ शामिल है जिनका ब्यौरा निर्यात के पहले सीएसपी के द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को दिया जाता है';

(ii) सी एस पी के निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए सामान्य सेवा के उपयोगकर्ताओं द्वारा किए निर्यात की संगणना तभी की जाएगी जबकि सामान्य सेवा प्रदाता के उपयोगकर्ताओं के संबंधित शिपिंग बिलों में सी एस पी के प्राधिकार का विवरण निहित होगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पहले उपयोगकर्ताओं के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा; और

(iii) इस अधिसूचना के संदर्भ में प्राधिकरण के अंतर्गत गिने गए निर्यात को सीएसपी या उपयोगकर्ता को विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के तहत जारी किए गए अन्य सभी प्राधिकरणों के अंतर्गत विशिष्ट निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा;

(II) भौतिक निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में या विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.04(I) निर्दिष्ट भारतीय रुपये में निर्यात आय प्राप्त की जाएगी। हालांकि प्राधिकरणों में जहां एकीकृत कर और माल और सेवा कर मुआवजा उपकर से छूट का लाभ नहीं लिया जाता है, आपूर्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को भी निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए गिना जाएगा; नामतः:-

(क) मान्य निर्यात, नामतः, -

(i) अग्रिम प्राधिकार या वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ii) ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपी को माल की आपूर्ति।

(iii) आर्थिक कार्य विभाग(डी इ ऐ), वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों या कोषों द्वारा उन एजेंसियों या कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त

पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति, जहाँ विधिक करारों में सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन का प्रावधान है;

(iv) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों या कोषों द्वारा उन एजेंसियों या कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्करों (प्रमुख ठेकों की एकमात्र जिम्मेदारी) की आपूर्ति तथा उन्हें लगाना जहाँ बोलियां विदेश में उत्पादित माल के लिए डेलीवरी ड्यूटी पेड (डी डी पी) कीमतों के आधार पर आमंत्रित कर मूल्यांकन किया गया जाता हो;

(v) किसी भी परियोजना अथवा उद्देश्य जिनके संबंध में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा-शुल्क दिनांक 30<sup>th</sup> जून, 2017 समय समय पर यथा संशोधित द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन शून्य सीमा शुल्क के साथ ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और जहाँ आपूर्तियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया का अनुसरण करके की जाती हैं, के लिए माल की आपूर्तियां;

(vi) दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, समय समय पर यथा संशोधित, के क्रम संख्या 598 पर दी गई सूची 31 में विनिर्दिष्ट मैगा विद्युत परियोजनाओं को लगाने के लिए माल की आपूर्ति इस शर्त के अधीन कि मैगा विद्युत परियोजना उक्त अधिसूचना के विनिर्दिष्ट क्षमता की दहलीज़ सीमा के अनुरूप हो। यह आपूर्ति आई सी बी प्रक्रिया के अधीन की जानी चाहिए। आई सी बी की यह शर्त आदेशात्मक नहीं होगी यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से प्रदान की जानी निश्चित की गई है अथवा यदि यह परियोजना को टैरिफ आधारित बिडिंग के माध्यम से प्रदान किया गया है;

(vii) अधिसूचना सं. 84/97-सीमा शुल्क, दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं या आधिकारिक उपयोग के लिए माल की आपूर्ति;

(viii) राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02 के खंड (ज) में प्रावधान किया गया है;

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति बशर्ते कि सरल विनिमय वाली विदेशी मुद्रा में वसूली हो;

(ग) आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी विनिमय; और

(घ) ऐसी सेवाओं के लिए रुपये में प्राप्त भुगतान जो विदेशी व्यापार नीति के पैरा 5.04(ट) में विनिर्दिष्ट हैं.

(ङ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.04(ल) निर्दिष्ट किए गए भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय।

(घ) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2023 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 01/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा किया है;

(ड.) "प्रक्रिया हैंड बुक" से अभिप्राय प्रक्रिया हैंड बुक, 2023 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना सं. 01/2023, दिनांक 31<sup>st</sup> मार्च, 2023 के द्वारा किया है;

(च) "विनिर्माण" से वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति, के पैरा 11.31 में परिभाषित है;

(छ) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

**सारणी 1**

क्र.सं.	माल का विवरण
1	उत्पादन, पूर्व-उत्पादन और उत्पादन के पश्चात के लिए पूंजीगत माल
2	आयातक द्वारा पूंजीगत माल के रूप में एसेम्बल करने के लिए सेमी नॉक डाउन (एस के डी) / पूरी तरह से नॉक डाउन (सी के डी) के स्वरूप में पूंजीगत माल
3	ऐसे आयातित, एसेम्बलड अथवा उत्पादित पूंजीगत माल के रख - रखाव के लिए वास्तव में आयातित और अपेक्षित क्रम सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल के कल पुर्जे
4	आयातक के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के लिए अपेक्षित कल पुर्जे

**सारणी 2**

क्र.सं.	पत्तन, आईसीडी, एलसीएस	जहां स्थित हैं
1	समुद्री बंदरगाह	बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दाहेज, [धामरा, धर्मतार, [दीघी, गोपालपुर]] [हल्दिया (कोलकाता बंदरगाह का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स), हजीरा (सूरत)], काकीनाडा, कांडला, कट्टपल्ली (तमिलनाडु), कोलकाता, कृष्णापट्टनम, एन्नोर (तमिलनाडु), कराईकल (पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश), मगदल्ला, मैंगलोर, मरमुगोआ, मुलद्वारका, मुंबई, मुंद्रा, नागपट्टनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपावाव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और वडीनार।
2	विमानपत्तन	अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुंबई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी और विशाखापट्टनम.
3	लैंड कंटेनर डिपो	आगरा, अहमदाबाद, अनापथी (आंध्र प्रदेश), मेलपक्कम गांव अरक्कोनम तालुक), वेल्लोर जिला(, बाबरपुर, बेंगलुरु, भदोही, भर्तिंडा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, चेटीपलयम (तमिलनाडु), छेहरता (अमृतसर), कोयम्बटूर, दादरी, दप्पर (डेराबस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), दिल्ली, धनद राऊ (जिला इंदौर), दिघी (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गडी हरसरू, गौहाटी, गुंटूर, होसुर (तमिलनाडु), हैदराबाद, इरुगुर गांव (तमिलनाडु), इरुंगट्टुकोट्टई एसआईपीसीओटी ) औद्योगिक पार्क, कन्नमबक्कम गांव, श्रीपेरंबटूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु(, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कलिंगनगर, कानपुर, करूर, खेड़ा पीथमपुर), जिला धार(, कोटा , कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मालनपुर, मंडीदीप (जिला रायसेन), मारीपलेम गांव (जिला गुंटूर के एडलापडु तालुक में), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, नट्टकम गांव (कोट्टायम तालुक और जिला), पाटली (गुडगांव), पिंपरी (पुणे), पीतमपुर (इंदौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रुद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगनालुर, सूरत, सूरजपुर, तालेगांव (जिला पुणे), थुडियालुर (तमिलनाडु), तिरुपुर, टोंडियारपेट )TNPM) ) चेन्नई में, तुम्ब गांव तालुका उंबरगांव), जिला वलसाड(, तूतिकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वीरपंडी तमिलनाडु) और वालुज (औरंगाबाद)।



4	भू सीमा शुल्क स्टेशन	अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबांधा, डावकी, घोजाडांगा, हिल्ली, जोगबनी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सोनौअली), पेट्रापोल, रानाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद और सुतारखंडी.
---	----------------------	---

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2023

**No. 26/2023 - Customs**

**G.S.R. 259(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table 1 annexed hereto, from, -

- (i) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act); and
- (ii) the whole of the additional duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, when specifically claimed by the importer;
- (iii) the whole of integrated tax and the goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub-sections (7) and (9) of section 3 of the Customs Tariff Act.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely: -

- (1) that the goods imported are covered by a valid authorisation issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of Chapter 5 of the Foreign Trade Policy permitting import of goods at zero customs duty.
- (2) that the authorisation is registered at the port of import specified in the said authorisation and the goods, which are specified in the Table 1 annexed hereto, are imported within validity of the said authorisation and the said authorisation is produced for debit by the proper officer of customs at the time of clearance:

Provided that the catalyst for one subsequent charge shall be allowed, under the authorisation in which plant, machinery or equipment and catalyst for initial charge have been imported, except in cases where the Regional Authority issues a separate authorisation for catalyst for one subsequent charge after the plant, machinery or equipment and catalyst for initial charge have already been imported.

- (3) that the goods imported shall not be disposed of or transferred by sale or lease or any other manner till export obligation is complete.

- (4) that the importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs binding himself to comply with all the conditions of this notification as well as to fulfill export obligation on Free on Board (FOB) basis equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the authorisation, or for such higher sum as may be fixed or endorsed by the Regional Authority in terms of Para 5.15 of the Handbook of Procedures, within a period of six years from the date of issue of Authorisation, in the following proportions, namely:-

S. No.	Period from the date of issue of Authorisation	Minimum export obligation to be fulfilled
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 <sup>st</sup> to 4 <sup>th</sup> year	50%
2.	Block of 5 <sup>th</sup> and 6 <sup>th</sup> year	Balance EO:

Provided that in case the authorisation is issued to a Common Service Provider (CSP), it shall execute the bond with bank guarantee and the bank guarantee shall be equivalent to 100 per cent. of the duty foregone, and the bank guarantee shall be given by CSP or by anyone of the users or a combination thereof, at the option of the CSP:

Provided further that the export obligation shall be 75 per cent. of the normal export obligation specified above when fulfilled by export of following green technology products, namely, Solar Energy Generating Systems and parts or Equipments thereof, Wind Energy Generating Systems and parts or equipment thereof, LED lights of various kind, Vapour Absorption Chillers, Waste Heat Boiler, Waste Heat Recovery Units, Unfired Heat Recovery Steam Generators, Water Treatment Plants, Battery Electric Vehicles (BEV) [other than Hybrid Electric Vehicles (HEVs) and Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)] of all types, Vertical Farming equipment, Wastewater Treatment and Recycling, Rainwater harvesting system and Rainwater Filters, and Green Hydrogen:

Provided also that for units located in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Jammu and Kashmir and Ladakh, the export obligation shall be 25 per cent. of the normal export obligation specified above:

Provided also that where a unit holding Export Promotion Capital Goods authorisation and have been admitted under provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [31 of 2016] for commencement of insolvency proceedings and in respect of whom the resolution plan has been approved under section 31 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 by Adjudicating Authority shall be permitted to relief, concessions and waivers in accordance with the resolution plan approved or finalized by Adjudicating Authority or Appellate Authorities as the case may be.

(5) that if the importer does not claim exemption from the additional duty leviable under sub-sections (1), (3), (5), (7) and (9) of section 3 of the Customs Tariff Act, the additional duty so paid by him shall not be taken for computation of the net duty saved for the purpose of fixation of export obligation provided the Input Tax Credit of additional duty paid has not been taken.

(6) that the importer, including a CSP, produces within thirty days from the expiry of each block from the date of issue of authorisation or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the sub-para (4) of para 2, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs equal to an amount which bears the same proportion to the duties leviable on the goods, but for the exemption contained herein, which the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation, together with interest at the rate of fifteen per cent. per annum from the date of clearance of the goods.

(7) that where the importer fulfills 75 per cent. or more of the export obligation as specified in condition (4) [over and above 100 per cent. of the average export obligation] within half of the period specified for export obligation as mentioned in sub-para (4) of para 2, his balance export obligation shall be condoned and he shall be treated to have fulfilled the entire export obligation:

Provided that the benefit of reduced export obligation in terms of second and third provisos of sub-para (4) of para 2 above is not availed.

(8) that the capital goods imported, assembled or manufactured, are installed and put to use, after their import, in the importer's factory or premises and a certificate from Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over importer's factory or premises or from an independent Chartered Engineer, is produced within a period of six months from the date of completion of imports before the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs at the port of import confirming such installation and use of the capital goods in the importer's factory or premises:

Provided that where the Regional Authority grants extension of the said period beyond six months from the date of completion of imports, the said overall period shall be extended by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs as the case may be:

Provided further that an importer (including an importer who is a CSP) opting for the independent Chartered Engineer's certificate shall send a copy of the certificate, upon its issuance, to the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over importer's factory or premises, as intimation or record:

Provided also that in case of import of spares, the installation certificate shall be produced within three years from the date of import:

Provided also that in the case of manufacturer exporter and merchant exporter having supporting manufacturers or in the case of import of irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products or in the case of importer rendering services, the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address is endorsed, prior to installation, by the Regional Authority on the authorisation referred to in sub-para (1) of para 2. This would apply even when Regional Authority endorses a change in the factory or premises or person. The name and address of such

other person shall also be mentioned on the relevant shipping bills. This shall not apply to a CSP:

Provided also that agro units located in Agri Export Zones or service providers in Agri Export Zones may move the capital goods within the Agri Export Zones under intimation to the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, subject to the condition that the importer shall maintain accurate record of such movement.

(9) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed hereto or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction.

(10) that notwithstanding anything contained in sub-para (4) of para 2 above, where the Regional Authority grants extension of block-wise period for any block(s) or overall period of fulfillment of export obligation up to a period of two years, the said block-wise period or overall period of export obligation shall be extended by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that in respect of the units referred to in the fourth proviso to sub-para (4) of para 2 above, extension of overall period of export obligation shall not be allowed.

3. Where the goods specified in the Table 1 are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within three years from date of clearance of said goods:

Provided that at the time of re-export, the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to be the same as the goods which were imported.

*Explanation* - For the purpose of this notification, -

(A) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 11.08 of the Foreign Trade Policy;

(B) "Common Service Provider" (CSP) means a service provider who is designated or certified as a Common Service Provider by the DGFT - HQs, Department of Commerce in a Town of Export Excellence or Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks (PM MITRA);

(C) "Export obligation", -

(I) means obligation on the importer to export to a place outside India, goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of capital goods imported in terms of this notification and the export obligation shall be over and above the average level of exports achieved by the importer in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including the extended period, if any and such average shall be the arithmetic mean of export performance in the last three years for the same and similar products:

Provided that in case of export of goods relating to handicraft, handlooms, industries covered under Khadi and Village Industries Commission (KVIC), agriculture, aquaculture (including fisheries), pisciculture animal husbandry and dairying, floriculture and horticulture, poultry, viticulture, sericulture, carpets, coir and jute, the importer shall not be required to maintain the average level of exports:

Provided also that in case of export of goods relating to aquaculture (including fisheries), the importer shall not be required to maintain the average level of exports subject to the condition that EPCG authorisation has been obtained for goods other than fishing trawlers, boats, ships and other similar items:

Provided also that the goods, excepting tools, imported under this notification by the aforesaid sectors, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled:

Provided also that exports made to such countries as notified by Director General of Foreign Trade, shall not be counted for fixing the average level of exports:

Provided also that exports against only such shipping bills which mention the authorisation number and date of the authorisation shall be counted for the fulfillment of the export obligation:

Provided also that in the case of authorisation issued to a CSP, -

(i) the reference to 'importer' in this Explanation shall be taken to mean a reference to 'CSP and specific users whose details are informed prior to export by CSP to the Regional Authority';

(ii) for the exports by users of the common service to be counted towards fulfilment of export obligation of CSP, the respective shipping bills of the users of common service shall contain the authorisation details of the CSP and the concerned Regional Authority shall be informed about the details of the users prior to such export; and

(iii) the exports counted against the authorisation in terms of this notification shall not be counted towards fulfillment of specific export obligations against all other authorisations issued to the CSP or user under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy

(II) shall be fulfilled through physical exports and the export proceeds realised in freely convertible currency or in Indian Rupees as are specified in para 5.04(l) of Foreign Trade Policy, however, in authorisations where exemption from integrated tax and goods and services tax compensation cess is not availed, the following categories of supplies, shall also be counted towards fulfilment of export obligation, namely:-

(a) deemed exports, namely:-

- (i) supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation;
- (ii) supply of goods to Export Oriented Units or Software Technology Parks or Electronics Hardware Technology Park or Bio-Technology Parks;
- (iii) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral Agencies or Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF, under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those Agencies or Funds where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;
- (iv) supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral Agencies or Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF, under ICB in accordance with procedures of those Agencies or Funds where bids have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;
- (v) supply of goods to any project or for any purpose in respect of which the Ministry of Finance by Customs Notification No. 50/2017-Customs dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, permits import of such goods at zero basic customs duty subject to conditions specified in the said notification and the supply is made under procedure of ICB;
- (vi) supply of goods required for setting up of any mega power project, as specified in the list 31 at Sl. No. 598 of Department of Revenue Notification No. 50/2017-Customs dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, provided such mega power project conforms to the threshold generation capacity specified in the said Notification and the supply shall be made under ICB procedure, however, ICB condition would not be mandatory if the requisite quantum of power has been tied up through tariff based competitive bidding or if the project has been awarded through tariff based competitive bidding;
- (vii) supply of goods for official use or to the projects funded by UN or International Organisation in terms of Notification No. 84/97-Customs dated the 11<sup>th</sup> November, 1997;
- (viii) supply of goods to nuclear power projects through National competitive bidding (NCB) or through ICB as provided in clause (g) of para 7.02 of Foreign Trade Policy;

(b) supply of Information Technology Agreement (ITA-1) items to Domestic Tariff Area, provided realisation is in free foreign exchange;

(c) royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for Research and Development (R&D) services;

(d) payments received in Rupee terms for such services as are specified in paragraph 5.04(k) of the Foreign Trade Policy; and

(e) export proceeds realised in India Rupees as are specified in paragraph 5.04(l) of the Foreign Trade Policy.

(D) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31st March, 2023;

(E) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedures, 2023 published by the Government of

India in the Ministry of Commerce and Industry vide public notice No. 01/2023, dated the 1st April, 2023;

(F) "Manufacture" has the same meaning as defined in paragraph 11.31 of the Foreign Trade Policy;

(G) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

TABLE 1

S. No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods for pre-production, production and post-production
2.	Capital goods in Semi Knocked Down (SKD) / Completely Knocked Down (CKD) conditions to be assembled into capital goods by the importer
3.	Spare parts of goods specified at Serial Nos.1 and 2 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured
4.	Spare parts required for the existing plant and machinery of the importer

TABLE 2

S.No.	Port, ICD, LCS	Located at
1.	Seaports	Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, [Dhamra,Dharamtar, [Dighi, Gopalpur]] [Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port), Hazira (Surat)], Kakinada, Kandla, Kattupalli (Tamil Nadu), Kolkata, Krishnapatnam, Ennore (Tamil Nadu), Karaikal (Union territory of Puducherry), Magdalla, Mangalore, Marmugoa, Muldwarka, Mumbai, Mundra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadarinar.
2.	Airports	Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Calicut, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum, Varanasi and Visakhapatnam.
3.	Inland Container Depots	Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Melpakkam Village (Arakkonam Taluk, Vellore District), Babarpur, Bengaluru, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamil Nadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dhannad Rau (District Indore), Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hosur (Tamil Nadu), Hyderabad, Irugur Village (Tamil Nadu), Irungattukottai (SIPCOT Industrial Park, Kattrambakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamil Nadu), Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Kalinganagar, Kanpur, Karur, Kheda (Pithampur, District Dhar), Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Marripalem Village(in Edlapadu Taluk of District Guntur), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Nattakkam Village (Kottayam Taluk and District), Patli (Gurgaon), Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Talegaon (District Pune), Thudiyalur (Tamil Nadu), Tirupur, Tondiarpet (TNPM) in Chennai, Tumb Village (Taluka Umbergoan, District Valsad), Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Veerapandi (Tamil Nadu) and Waluj (Aurangabad).
4.	Land Customs Stations	Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

**संख्या 27/ 2023 - सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 260(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.04ए के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र (इसके बाद उक्त प्राधिकार पत्र के रूप में संदर्भित) के सापेक्ष भारत में आयातित कपड़ों (इंटरलाइनिंग सहित) को संपूर्ण शुल्क से छूट देता है। उस पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (बाद में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है और उप-धाराओं (1) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से, धारा 3 की (3) और (5), धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत उस पर लगने वाला एकीकृत कर, धारा 3 की उप-धारा (9) के तहत उस पर लगने वाला माल और सेवा कर मुआवजा उपकर, उस पर लगने वाला सुरक्षा शुल्क धारा 8बी के तहत, धारा 9 के तहत लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए के तहत लगाए जाने वाले एंटी-डंपिंग शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरी तरह से छूट प्रदान करती है, अर्थात्: -

(i) कि डेबिट के लिए निकासी के समय उचित अधिकारी के समक्ष उक्त प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया है;

(ii) उक्त प्राधिकार पत्र केवल कपड़े के आयात के लिए है और इसमें, -

(क) उन मामलों में आयातक और सहायक निर्माता का नाम और पता जहां एक व्यापारी निर्यातक को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है; और

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 61 या 62 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के निर्यात किए जाने वाले कपड़ों का विवरण और अन्य विनिर्देश और निर्यात का विवरण, मात्रा और मूल्य;

(iii) कि आयातित फैब्रिक्स प्राधिकार पत्र में वर्णित विवरण और अन्य विनिर्देशों (जहां लागू हो) के अनुरूप हैं और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार हैं और उनका मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकार में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हैं;

(iv) आयातक आयातित कपड़े की निकासी के समय एक बांड निष्पादित करता है और उसके साथ ऐसी जमानत ऐसे रूप में प्रस्तुत करता है जो कि उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करता हो जिसके द्वारा अपने को इस बात के लिए बाध्य करता हो कि यदि इसमें निहित छूट न मिले तो वह ऐसी आयातित सामग्री से संबंधित उस राशि का भुगतान कर देगा जो कि उस पर लगने वाले शुल्क के बराबर हो और यदि इस अधिसूचना में निर्धारित शर्त पूरा नहीं होती है तो उक्त सामग्री के निकासी की तारीख से 15 प्रतिशित वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करेगा।

बशर्ते कि किसी व्यापारी निर्यातक को जारी किए गए उक्त प्राधिकरण के संबंध में, इस अधिसूचना के अनुसार आयातक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बांड को व्यापारी निर्यातक द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा और सहायक निर्माता इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्य होंगे।

(v) कि ऐसा आयात और निर्यात अधिसूचना सं. 26/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 01.04.2023 की सारणी 2 में उल्लिखित समुद्री पत्तनों, हवाई अड्डों, इनलैंड कंटेनर डिपो या लैंड कस्मटम्स स्टेशन्स के माध्यम से या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के खण्ड 4 में अधिसूचित विशेष आर्थिक जोनों से होता हो।

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश या एक सार्वजनिक नोटिस और उसके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी अन्य बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है।

(vi) कि ऐसा विदेश व्यापार नीति निर्यात के तहत पैरा 4.04क (ii) के अनुसार अधिसूचित स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मानदंड नॉर्म (एसआईओएन) या मानकों के पूर्व निर्धारण या स्व-घोषणा के आधार पर कपड़ों पर लगाए गए आयात पूर्व शर्तों के अनुसार ही किया गया हो।

(vii) उक्त प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट निर्यात दायित्व (मूल्य और मात्रा दोनों शर्तों में) उक्त प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर पूरा किया जाता है जो क्षेत्रीय प्राधिकार पत्र द्वारा उत्पादों के भौतिक निर्यात के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है (जिसमें पूर्व-आयातित कपड़ा भौतिक रूप से शामिल है) भारत में निर्मित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 61 या 62 के अंतर्गत आता है जो उक्त प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट हैं;

(viii) आयातक अनुमत अवधि की समाप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर, सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए निर्यात दायित्व के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। दायित्व, या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि सीमा शुल्क के उक्त उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अनुमति दे सकते हैं;

(ix) उक्त प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उक्त कपड़े को स्थानांतरित या बेचा नहीं जाएगा;

बशर्ते कि संबंधित माल और सेवा कर प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के अधीन जॉब वर्क के लिए सामग्री के हस्तांतरण की अनुमति देने वाले उक्त फैब्रिक्स को प्रसंस्करण के लिए एक जॉब वर्कर को हस्तांतरित किया जा सकता है;

2. जहां ऐसे कपड़ों को दोषयुक्त या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उक्त कपड़ों को इसके निकासी की तारीख से या ऐसी विस्तारित अवधि जिसके लिए सीमा शुल्क आयुक्त अनुमति दे और वह छह माह से अधिक नहीं हो, के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस कर सकता है।

बशर्ते कि पुनर्निर्यात के समय, कपड़े की पहचान उसी कपड़े के रूप में की जाती है जिसे सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण, - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(i) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी की गई विदेश व्यापार नीति से है।

(ii) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक या उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

### No. 27/2023 - Customs

**G.S.R. 260(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts fabrics (including interlining) imported into India against a valid Special Advance Authorisation (hereinafter referred to as the said authorisation) issued by the Regional Authority in terms of paragraph 4.04A of the Foreign Trade Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3, integrated tax leviable thereon under sub-section(7) of section 3, the goods and services tax compensation cess leviable thereon under sub-section (9) of section 3, safeguard duty leviable thereon under section 8B, countervailing duty leviable thereon under section 9 and anti-dumping duty leviable thereon under section 9A of the Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer at the time of clearance for debit;

(ii) that the said authorisation is meant for import of fabric only and bears,-

(a) the name and address of the importer and the supporting manufacturer in cases where the authorisation has been issued to a merchant exporter; and

(b) the description and other specifications of the fabrics to be imported and the description, quantity and value of exports of the product falling under Chapter 61 or 62 of the said First Schedule to the Customs Tariff Act;

(iii) that the fabrics imported corresponds to the description and other specifications (where applicable) mentioned in the authorisation and are in terms of para 4.12 of the Foreign Trade Policy and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation;

(iv) that the importer at the time of clearance of the imported fabric executes a bond with such surety or security and in such Form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen per cent. per annum from the date of clearance of the said materials:

Provided that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter, the bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the merchant exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification;

(v) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as specified in the Table 2 annexed to the Notification No. 26/2023-Customs dated 1st April, 2023 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other Seaport, Airport, Inland Container Depot or through a Land Customs Station within his jurisdiction;

(vi) that the export is made subject to pre-import condition on the fabrics in terms of notified Standard Input Output Norms (SION) or under prior fixation of norms or on the basis of self-declaration as per para 4.04A(ii) of Foreign Trade Policy for fabric only;

(vii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority through physical exports of products (in which the preimported fabric is physically incorporated) falling under Chapter 61 or 62 of the First Schedule to the Customs Tariff Act manufactured in India which are specified in the said authorisation;

(viii) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(ix) that the said authorisation shall not be transferred and the said fabrics shall not be transferred or sold;

Provided that the said fabrics may be transferred to a job worker for processing subject to complying the conditions specified in the relevant goods and services tax provisions permitting transfer of materials for job work;

2. Where the fabrics are found defective or unfit for use, the said fabrics may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said fabrics or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export, the fabrics are identified as the same fabric which was imported to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.

*Explanation*, – For the purposes of this notification,–

(I) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31st March, 2023;

(II) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation under the said Act.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.



**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

**सं. 24/2023 – सीमा शुल्क (गै.टे.)**

**सा.का.नि. 261(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उपधारा (1) (एतदपश्चात् अधिनियम के रूप में संदर्भित), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना (एतदपश्चात् योजना के रूप में संदर्भित), के तहत निर्यात किए गए माल के लिए क्रेडिट जारी करने का तरीका ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01 (घ) में निर्दिष्ट है, अधिसूचित करती है।

2. ऐसा ड्यूटी क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, यथा: -

(1) कि ड्यूटी क्रेडिट जारी किया गया हो जब-

(क) निर्यातित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग की जानेवाली किसी भी सामग्री पर या भारत में ऐसे माल पर कोई प्रक्रिया करने के लिए, किसी भी शुल्क या कर या उगाही की छूट के बदले, जहां ऐसा शुल्क या कर या उगाही किसी अन्य योजना के तहत छूट प्राप्त नहीं है, हो छोड़ी या जमा नहीं की गई है;

(ख) विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट 4 आर (एतदपश्चात् परिशिष्ट के रूप में संदर्भित) में अधिसूचित माल के निर्यात के नामे, उक्त परिशिष्ट के तहत अधिसूचित संबंधित दर और उपरी सीमा पर;

बशर्ते कि योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की गणना के लिए उक्त माल का मूल्य उसके घोषित निर्यात एफओबी मूल्य या उक्त माल के बाजार मूल्य के 1.5 गुना तक हो, जो भी कम हो;

(ग) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में मद स्तर पर एक निर्यातक द्वारा योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के दावे के नामे उचित घोषणा प्रदान करके;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किये गए, 1 जनवरी 2021 या उसके बाद के शिपिंग बिल या निर्यात के बिल के नामे, और जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत निर्यात के लिए माल की निकासी और लदान की मंजूरी की अनुमति का आदेश दिया गया है;

(ङ.) सीमा शुल्क द्वारा, आवश्यक जांच के पश्चात दावे की अनुमति दी गई है, जिसमें उचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन का आधार शामिल है, तथा निर्यात घोषणा पत्र या निर्यात रिपोर्ट दाखिल करने के बाद;

(च) ड्यूटी क्रेडिट, ई-स्क्रिप या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर के संबंध में निर्मित किए किसी भी नियम या विनियमनों के अनुसार;

(2) यह कि इस प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनुसूची के तहत भारत में आयातित माल पर लगने वाले सीमा शुल्क ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जाएगा;

(3) यह कि इसके साथ संलग्न तालिका में सूचीबद्ध निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगे;

(4) यह कि परिशिष्ट में अधिसूचित माल के निर्यात के नामे योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत भारत में ऐसे माल की बिक्री आय की प्राप्ति के लिए अनुमत अवधि के अधीन होगा, ऐसा न करने पर ड्यूटी क्रेडिट अपात्र समझा जाएगा;

(5) यह कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किए जाते हैं जो सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर आयात बिल और शिपिंग बिल अथवा निर्यात के बिल को प्रस्तुत करने और संसाधित करने की अनुमति देते हैं;

(6) यह कि निर्यातक द्वारा पहले निर्यात किए गए माल के लिए बिक्री आय की प्राप्ति उक्त निर्यातक द्वारा हो चुकी हो, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमत अवधि या उक्त अवधि के किसी भी विस्तार सहित, समाप्त हो गई हो;

बशर्ते कि सीमा शुल्क द्वारा ड्यूटी क्रेडिट पहले किए गए माल के निर्यात के नामे, बिक्री आय के अप्राप्त हिस्से से संबंधित ड्यूटी क्रेडिट की अपात्र राशि को घटाकर बची हुई राशि जारी किया जाएगा;

बशर्ते कि प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क के पास जोखिम मूल्यांकन के आधार पर या जांच के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि निर्यात माल पर एक निर्यातक द्वारा किए गए ड्यूटी क्रेडिट का दावा वास्तविक नहीं हो सकता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे निर्यातों की बिक्री आय की प्राप्ति के बाद ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति देने का निर्देश दे सकता है;

(7) नेपाल, भूटान और म्यांमार को निर्यात के लिए, योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, भारतीय निर्यातकों के पक्ष में नेपाल, भूटान और म्यांमार में आयातकों द्वारा केवल ऐसे माल के मूल्य के लिए स्थापित स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अपरिवर्तनीय लेटर ऑफ़ क्रेडिट के नामे बिक्री आय की वसूली पर दी जाएगी।

3. ड्यूटी क्रेडिट रद्द करना: (1) जहां कोई व्यक्ति अधिनियम या लागू समय में किसी अन्य कानून अथवा उसके तहत बनाए गए निर्यात के संबंध में, नियम या विनियम जो ड्यूटी क्रेडिट से संबंधित है या ई-स्क्रिप के संबंध में, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क के आयुक्त जिनका क्षेत्राधिकार ई-स्क्रिप का पंजीकरण के सीमा शुल्क स्टेशन पर हो, जांच के बाद उक्त ड्यूटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है।

(2) जहां ई-स्क्रिप को इस प्रकार रद्द किया जाता है, उक्त ई-स्क्रिप में ड्यूटी क्रेडिट राशि को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और सीमा शुल्क के उचित अधिकारी ऐसी ई-स्क्रिप में उपयोग की गई या इस प्रकार हस्तांतरित ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, उप-पैरा(1) के तहत जांच के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम अथवा लागू समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किए जानेवाले कार्रवाई की पूर्वधारणा के बिना, उक्त ई-स्क्रिप या ऐसे निर्यातक के इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर या इस प्रकार के ई-स्क्रिप से हस्तांतरित किसी ड्यूटी क्रेडिट के प्रचालन को स्थगित कर सकते हैं।

4. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली: (1) जहां किसी भी कारण से निर्यातक के हक से अधिक ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति दी गई है, निर्यातक इस तरह की अनुमत अधिक राशि ब्याज सहित स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, यह अधिनियम की धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट के उस हिस्से पर, जिसका उपयोग या हस्तांतरण किया गया है, भुगतान करेगा और जहां निर्यातक, जैसा लागू हो, ब्याज सहित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, यह अधिनियम की धारा 142 में उपबंधित तरीके से वसूल की जाएगी।

5. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली, जहां निर्यात आय प्राप्त नहीं की गई हो:- (1) जहां एक निर्यातक को ड्यूटी क्रेडिट की राशि की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे निर्यात माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि के भीतर भारत में निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, निर्यातक, स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, उक्त अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए, ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की राशि चुकाएगा।

(2) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्री आय की प्राप्ति के लिए उक्त अवधि का कोई विस्तार दिया गया है और निर्यातक सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को इस तरह के विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और यदि उक्त बिक्री आय की प्राप्ति ऐसी विस्तारित अवधि में नहीं की जाती है, निर्यातक उक्त अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर उक्त ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की उक्त राशि का भुगतान करेगा।

(3) ऐसे मामले जहाँ पूरी बिक्री आय प्राप्त नहीं हुई हो लेकिन बिक्री की आय का एक हिस्सा प्राप्त किया गया हो, तो वसूल किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की राशि अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि के उस हिस्से के बराबर होगी, जिसका अनुपात वही होगा जो अप्राप्त बिक्री आय का कुल बिक्री आय से होता है।

(4) जहाँ निर्यातक पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर ड्यूटी क्रेडिट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, उक्त ड्यूटी क्रेडिट को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और इसे उक्त ब्याज के साथ, जैसा कि अधिनियम की धारा 142 में दिया गया है, वसूल किया जाएगा।

6. किसी भी वसूली के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि पैरा 4 और 5 में प्रावधान किया गया है, ऐसे निर्यातक को किसी भी आगामी निर्यातों पर आगे ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी वसूली नहीं हो जाती तथा निर्यातक एवं अंतरिती के पास कोई अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट ऐसी वसूली के लंबित रहने तक स्थगित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "दावा" का अर्थ है योजनाओं के तहत एक निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में आइटम स्तर पर उचित घोषणा प्रदान कर के ड्यूटी क्रेडिट का दावा;

(ख) "ड्यूटी क्रेडिट" का अर्थ है योजनाओं के तहत दावे के नामे सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर" का अर्थ है सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में लेजर जो उस व्यक्ति से संबंधित है जो ड्यूटी क्रेडिट प्राप्तकर्ता है या जिस व्यक्ति को ड्यूटी क्रेडिट स्थानांतरित किया गया है;

(घ) "ई-स्क्रिप" का अर्थ है, ड्यूटी क्रेडिट के लिए लेजर में बनाई गई स्क्रिप, जैसा कि अधिनियम की धारा 28कक की व्याख्या 1 में उल्लेखित है;

(ङ.) "निर्यात घोषणा पत्र" या "निर्यात रिपोर्ट" का अर्थ अधिनियम की धारा 41 में उल्लेखित है;

(च) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी की गई विदेश व्यापार नीति से है;

(छ) "उचित अधिकारी" का अर्थ है सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त;

#### तालिका

क्र. स.	ड्यूटी क्रेडिट के लिए अपात्र निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र
(1)	(2)
1.	माल, जो आईटीसी-एचएस में निर्यात नीति की अनुसूची -2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं
2.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत आनेवाले आयातित माल का निर्यात
3.	ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ है ऐसे निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन भारत के रास्ते ट्रांस-शिप किए गए हैं
4.	न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन माल

5.	विदेश व्यापार नीति के तहत डीम्ड निर्यात
6.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव-प्रौद्योगिकी पार्क / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित किसी भी इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
7.	सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई के रूप में लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
8.	प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति के तहत जारी अग्रिम प्राधिकरण या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत निर्यात किया गया माल
9.	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्मित तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की इकाइयों को आपूर्ति किया गया माल
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / निर्यात उन्मुख इकाई / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव-प्रौद्योगिकी पार्क / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्मित और डीटीए इकाइयों के माध्यम से निर्यात किया गया माल
11.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के तहत एक भंडारण क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण रूप से निर्मित माल
12.	अधिसूचना सं. 32/1997-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 1997 का लाभ उठाने वाले माल
13.	माल, जिसके लिए झूठी क्रेडिट का दावा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात बिल में दर्ज नहीं किया गया है
14.	माल जो विनिर्माण के बाद उपयोग में लिया गया है।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2023

**No. 24/2023-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 261(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the manner of issue of duty credit for goods exported under the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (hereinafter referred to as the Scheme), subject to such conditions and restrictions as specified herein, in accordance with paragraph 4.01(d) of the Foreign Trade Policy.

**2.** Such duty credit shall be subject to the following conditions, namely:-

(1) that the duty credit is issued -

(a) in lieu of remission of any duty or tax or levy, chargeable on any material used in the manufacture or processing of goods or for carrying out any operation on such goods in India that are exported, where such duty or tax or levy is not exempted, remitted or credited under any other Scheme;

(b) against export of goods notified in Appendix 4R (hereinafter referred to as the Appendix) of the Foreign Trade Policy, at the respective rate and cap notified under the said Appendix:

Provided that the value of the said goods for calculation of duty credit to be allowed under the Scheme shall be the declared export FOB value of the said goods or up to 1.5 times the market price of the said goods, whichever is less;

(c) against claim of duty credit under the Scheme made by an exporter by providing the appropriate declaration at the item level in the shipping bill or bill of export in the customs automated system;

(d) against the shipping bill or bill of export, presented under section 50 of the said Act where the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act has been made;

(e) after the claim is allowed by Customs upon necessary checks, including on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria, and after filing of export manifest or export report;

(f) in accordance with any rules or regulations made in relation to duty credit, e-scrip or electronic duty credit ledger;

(2) that such duty credit shall be used for payment of the duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) on goods when imported into India;

(3) that the export categories or sectors listed in Table annexed hereto shall not be eligible for duty credit under the Scheme;

(4) that the duty credit allowed under the Scheme against export of goods notified in the Appendix shall be subject to realisation of sale proceeds in respect of such goods in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), failing which such duty credit shall be deemed to be ineligible;

(5) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations which allow the bill of entry and shipping bill or bill of export to be presented and processed electronically on the customs automated system;

(6) that the exporter has realised the sale proceeds against export of goods made earlier by the said exporter where the period allowed for realisation, including any extension of the said period by the Reserve Bank of India, has expired:

Provided that duty credit shall be issued by Customs in excess of the ineligible amount of duty credit pertaining to the unrealised portion of sale proceeds against export of goods made earlier:

Provided further that if the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs has reason to believe, on the basis of risk evaluation or on the basis of enquiry, that the claim of duty credit made by an exporter on export goods may not be bona fide, he may direct, for reasons to be recorded in writing, to allow duty credit after realisation of sale proceeds of such exports;

(7) that duty credit under the Scheme for exports made to Nepal, Bhutan and Myanmar shall be allowed only upon realisation of sale proceeds against irrevocable letters of credit in freely convertible currency established by importers in Nepal, Bhutan and Myanmar in favour of Indian exporters for the value of such goods.

**3. Cancellation of duty credit.** - (1) Where a person contravenes any of the provisions of the Act or any other law for the time being in force or the rules or regulations made thereunder in relation to exports to which the duty credit relates, or in relation to the e-scrip, the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs having jurisdiction over the customs station of registration of the e-scrip may, after enquiry, pass an order to cancel the said duty credit or e-scrip.

(2) Where the e-scrip is so cancelled, the duty credit amount in the said e-scrip shall be deemed never to have been allowed and the proper officer of Customs shall proceed to recover the duty credit amount used in such e-scrip or transferred from such e-scrip.

(3) The proper officer of Customs may, without prejudice to any other action that may be taken under this Act or any other law for the time being in force, suspend the operation of the said e-scrip or the electronic duty credit ledger of such exporter or any duty credit transferred from such e-scrip, during pendency of the enquiry under sub-para (1).

**4. Recovery of amount of duty credit.** - (1) Where an amount of duty credit has, for any reason, been allowed in excess of what the exporter is entitled to, the exporter shall repay the amount so allowed in excess, himself or on demand by the proper officer, along with interest, at the rate as fixed under section 28AA of the said Act for the purposes of that section, on that portion of duty credit allowed in excess, which has been used or transferred, and where the exporter fails to repay the amount along with interest, as applicable, it shall be recovered in the manner provided in section 142 of the said Act.

**5. Recovery of amount of duty credit where export proceeds are not realised.** - (1) Where an amount of duty credit has been allowed to an exporter but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realized by the exporter in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the exporter shall, himself or on demand by the proper officer, repay the amount of duty credit, along with interest, at the rate as fixed under section 28AA of the said Act for the purposes of that section, within fifteen days of expiry of the said period.

(2) In case any extension of the said period for realisation of sale proceeds has been given by the Reserve Bank of India and the exporter produces evidence of such extension to the proper officer, and if the said sale proceeds are not realised in such extended period, the exporter shall repay the said amount of duty credit along with the said interest, within fifteen days of expiry of the said period.

(3) If a part of the sale proceeds has been realized, the amount of duty credit to be recovered shall be the amount equal to that portion of the amount of duty credit allowed which bears the same proportion as the portion of the sale proceeds not realized bears to the total amount of sale proceeds.

(4) Where the exporter fails to repay the duty credit amount within the said period of fifteen days, the said duty credit shall be deemed never to have been allowed and it shall be recovered, along with the said interest, in the manner as provided in section 142 of the said Act.

**6. During the pendency of any recovery,** as provided in paras 4 and 5, no further duty credit, on any subsequent exports, shall be allowed to such exporter till the time such recovery is made and any unutilised duty credit with the exporter shall be suspended pending such recovery.

*Explanation* – For the purposes of this notification, -

(a) “Claim” means a claim of duty credit under the Scheme made by an exporter in the shipping bill or bill of export by providing the appropriate declaration at the item level in the said shipping bill or bill of export in the customs automated system;

(b) “Duty credit” means the amount of credit of duty allowed by Customs against a claim under the Scheme;

(c) “Electronic duty credit ledger” means the ledger in the customs automated system relating to a person who is the recipient of duty credit or to person to whom the duty credit is transferred;

(d) “E-scrip” means the scrip, created in the ledger for duty credit, as mentioned in *Explanation* 1 of section 28AAA of the said Act;

(e) “Export manifest” or “export report” means the reference to the terms used in Section 41 of the said Act;

(f) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31st March, 2023;

(g) “Proper officer” means Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs.

**TABLE**

Sl. No.	Export categories or sectors ineligible for duty credit
(1)	(2)
1.	Goods which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC-HS
2.	Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of Foreign Trade Policy
3.	Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country but trans-shipped through India
4.	Goods subject to minimum export price or export duty
5.	Deemed exports under Foreign Trade Policy
6.	Goods manufactured or exported by any of the units situated in Special Economic Zone/ Free Trade Warehousing Zone/Electronic Hardware Technology park/Bio-Technology park/ Export Processing Zone
7.	Goods manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent Export Oriented Unit
8.	Goods exported under Advance Authorisation or Duty Free Import Authorisation issued under the relevant Foreign Trade Policy
9.	Goods manufactured and supplied by units in Domestic Tariff Area to units in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone
10.	Goods manufactured in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone / Export Oriented Unit / Electronic Hardware Technology Park /Bio-Technology Park/ Export Processing Zone and exported through DTA unit
11.	Goods manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)
12.	Goods availing the benefit of the notification No. 32/1997-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> April, 1997
13.	Goods for which claim of duty credit is not filed in a shipping bill or bill of export in the customs automated system
14.	Goods that have been taken into use after manufacture.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

**सं. 25/2023 – सीमा शुल्क (गै.टे.)**

**सा.का.नि. 262(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उपधारा (1) (एतदपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यातित माल पर राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी पर छूट के लिए योजना (एतदपश्चात् योजना के रूप में संदर्भित) के तहत निर्यात किए गए माल के लिए ड्यूटी क्रेडिट जारी करने का तरीका, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 13 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी में निर्दिष्ट है, अधिसूचित करती है।

2. ऐसा ड्यूटी क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, यथा: -

(1) कि ड्यूटी क्रेडिट जारी किया गया हो जब-

(क) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (संस्करण II), दिनांक 08 मार्च, 2019 की अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में यथा सूचीबद्ध परिधान तथा मेड अप्स (एतदपश्चात् उक्त माल से संदर्भित) और उनकी दरों और सीमाओं के निर्यात के नामे:

बशर्ते कि योजना के तहत स्वीकृत किए जानेवाले ड्यूटी क्रेडिट की गणना के लिए उक्त माल का मूल्य उसके घोषित निर्यात फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या उक्त माल के बाजार मूल्य के 1.5 गुना तक हो, जो भी कम हो;

(ख) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में मद स्तर पर एक निर्यातक द्वारा योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के दावे के नामे उचित घोषणा प्रदान करके;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किये गए, शिपिंग बिल या निर्यात के बिल के नामे, और जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत निर्यात के लिए माल की निकासी और लदान की अनुमति का आदेश दिया गया है;

(घ) सीमा शुल्क द्वारा, आवश्यक जांच के पश्चात् दावे की अनुमति दी गई है, जिसमें उचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन का आधार शामिल है, तथा निर्यात घोषणा पत्र या निर्यात रिपोर्ट दाखिल करने के बाद;

(ङ) ड्यूटी क्रेडिट, ई-स्क्रिप या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर के संबंध में जारी किए गए किसी भी नियम या विनियम के अनुसार;

(2) यह कि इस प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के तहत भारत में आयातित माल पर लगने वाले सीमा शुल्क ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जाएगा;

(3) यह कि इसके साथ संलग्न तालिका में सूचीबद्ध निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगे;

(4) यह कि योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (संस्करण II), दिनांक 08 मार्च, 2019 के तहत निर्यात किए गए माल के नामे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत भारत में ऐसे माल की बिक्री आय की प्राप्ति के लिए अनुमत अवधि के अधीन होगा, ऐसा न करने पर ड्यूटी क्रेडिट अपात्र समझा जाएगा;

(5) यह कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किए जाते हैं जो सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर आयात बिल और शिपिंग बिल अथवा निर्यात के बिल को प्रस्तुत करने और संसाधित करने की अनुमति देते हैं;

(6) यह कि निर्यातक द्वारा पहले निर्यात किए गए माल के लिए बिक्री आय की प्राप्ति उक्त निर्यातक द्वारा हो चुकी हो, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमत अवधि या उक्त अवधि के किसी भी विस्तार सहित, समाप्त हो गई हो:

बशर्ते कि सीमा शुल्क द्वारा ड्यूटी क्रेडिट पहले किए गए माल के निर्यात के नामे, बिक्री आय के अप्राप्त हिस्से से संबंधित ड्यूटी क्रेडिट की अपात्र राशि को घटाकर बची हुई राशि जारी किया जाएगा:

बशर्ते कि प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क के पास जोखिम मूल्यांकन के आधार पर या जांच के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि निर्यात माल पर एक निर्यातक द्वारा किए गए ड्यूटी क्रेडिट का दावा वास्तविक नहीं हो सकता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जानेवाले कारणों से ऐसे निर्यातों की बिक्री आय की प्राप्ति के बाद ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति देने का निर्देश दे सकता है;

(7) नेपाल, भूटान और म्यांमार को निर्यात के लिए, योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, भारतीय निर्यातकों के पक्ष में नेपाल, भूटान और म्यांमार में आयातकों द्वारा केवल ऐसे माल के मूल्य के लिए स्थापित स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अपरिवर्तनीय लेटर ऑफ़ क्रेडिट के नामे बिक्री आय की वसूली पर दी जाएगी।

3. ड्यूटी क्रेडिट रद्द करना: (1) जहां कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम या लागू समय में किसी अन्य कानून अथवा उसके तहत बनाए गए निर्यात के संबंध में, नियम या विनियम जो ड्यूटी क्रेडिट से संबंधित है या ई-स्क्रिप के संबंध में, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क के आयुक्त जिनका क्षेत्राधिकार ई-स्क्रिप का पंजीकरण के सीमा शुल्क स्टेशन पर हो, जांच के बाद उक्त ड्यूटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है।

(2) जहां ई-स्क्रिप को इस प्रकार रद्द किया जाता है, उक्त ई-स्क्रिप में ड्यूटी क्रेडिट राशि को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और सीमा शुल्क के उचित अधिकारी ऐसी ई-स्क्रिप में उपयोग की गई या इस प्रकार हस्तांतरित ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, उप-पैरा(1) के तहत जांच के लंबित रहने के दौरान, इस अधिनियम अथवा लागू समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किए जानेवाले कार्रवाई की पूर्वधारणा के बिना, उक्त ई-स्क्रिप या ऐसे निर्यातक के इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर या इस प्रकार के ई-स्क्रिप से हस्तांतरित किसी ड्यूटी क्रेडिट के प्रचालन को स्थगित कर सकते हैं।

4. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली: (1) जहां किसी भी कारण से निर्यातक के हक से अधिक ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति दी गई है, निर्यातक स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, इस तरह की अनुमत अधिक राशि ब्याज सहित उक्त अधिनियम की धारा 28क के तहत निर्धारित दर पर उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट के उस हिस्से पर, जिसका उपयोग या हस्तांतरण किया गया है, भुगतान करेगा और जहां निर्यातक, जैसा लागू हो, ब्याज सहित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, यह उक्त अधिनियम की धारा 142 में उपबंधित तरीके से वसूल की जाएगी।

5. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली, जहां निर्यात आय प्राप्त नहीं की गई हो:- (1) जहां एक निर्यातक को ड्यूटी क्रेडिट की राशि की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे निर्यात माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि के भीतर भारत में निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, निर्यातक, स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, उक्त अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 28क के तहत निर्धारित दर पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए, ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की राशि चुकाएगा।



(2) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्री आय की प्राप्ति के लिए उक्त अवधि का कोई विस्तार दिया गया है और निर्यातक, उचित अधिकारी को इस तरह के विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और यदि उक्त बिक्री आय की प्राप्ति ऐसी विस्तारित अवधि में नहीं की जाती है, निर्यातक उक्त अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर उक्त ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की उक्त राशि का भुगतान करेगा।

(3) ऐसे मामले जहाँ पूरी बिक्री आय प्राप्त नहीं हुई हो लेकिन बिक्री की आय का एक हिस्सा प्राप्त किया गया हो, तो वसूल किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की राशि अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि के उस हिस्से के बराबर होगी, जिसका अनुपात वही होगा जो अप्राप्त बिक्री आय का कुल बिक्री आय से होता है।

(4) जहां निर्यातक पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर ड्यूटी क्रेडिट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, उक्त ड्यूटी क्रेडिट को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और इसे उक्त ब्याज के साथ, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 142 में दिया गया है, वसूल किया जाएगा।

6. किसी भी वसूली के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि पैरा 4 और 5 में प्रावधान किया गया है, ऐसे निर्यातक को किसी भी आगामी निर्यातों पर आगे ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी वसूली नहीं हो जाती तथा निर्यातक के पास कोई अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट ऐसी वसूली के लंबित रहने तक स्थगित कर दिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "दावा" का अर्थ है योजना के तहत एक निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में आइटम स्तर पर उचित घोषणा प्रदान कर के ड्यूटी क्रेडिट का दावा;

(ख) "ड्यूटी क्रेडिट" का अर्थ है योजना के तहत दावे के नामे सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर" का अर्थ है सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में लेजर जो उस व्यक्ति से संबंधित है जो ड्यूटी क्रेडिट प्राप्तकर्ता है या जिस व्यक्ति को ड्यूटी क्रेडिट हस्तांतरित किया गया है;

(घ) "ई-स्क्रिप" का अर्थ है, ड्यूटी क्रेडिट के लिए लेजर में बनाई गई स्क्रिप, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 28कक की व्याख्या 1 में उल्लेखित है;

(ङ.) "निर्यात घोषणा पत्र" या "निर्यात रिपोर्ट" का अर्थ उक्त अधिनियम की धारा 41 में उल्लेखित है;

(च) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी की गई विदेश व्यापार नीति से है;

(छ) "परिधान तथा मेड अप्स" का अर्थ वही है जो कि भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 13 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी में परिधान/वस्त्रों तथा मेड अप्स के निर्यात पर लगाए जाने वाले राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी पर छूट के लिए योजना (आरओएससीटीएल) को बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया गया था, में दिया गया है;

(ज) "उचित अधिकारी" का अर्थ है सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त;

#### तालिका

क्र. सं.	ड्यूटी क्रेडिट के लिए अपात्र निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र
(1)	(2)
1.	माल, जो आईटीसी-एचएस में निर्यात नीति की अनुसूची -2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं

2.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत आनेवाले आयातित माल का निर्यात
3.	ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ है ऐसे निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन भारत के रास्ते ट्रांस-शिप किए गए हैं
4.	न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन माल
5.	विदेश व्यापार नीति के तहत मानित निर्यात
6.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित किसी भी इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
7.	सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई के रूप में लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
8.	प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति के तहत जारी अग्रिम प्राधिकरण या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत निर्यात किया गया माल: बशर्ते कि जहां अधिसूचना संख्या 27/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 2023 के अनुसार निर्यात दायित्वों के निर्वहन में विदेश व्यापार नीति 2023 के पैराग्राफ 4.04क के तहत जारी विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किया जाता है, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी, दिनांक 8 मार्च, 2019 की अनुसूची 3 और 4 में निर्दिष्ट आरओएससीटीएल योजना की दरें लागू होगी।
9.	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्मित तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की इकाइयों को आपूर्ति किया गया माल
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / निर्यात उन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्मित और डीटीए इकाइयों के माध्यम से निर्यात किया गया माल
11.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के तहत एक भंडारण क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण रूप से निर्मित माल
12.	अधिसूचना सं. 32/1997-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 1997 का लाभ उठाने वाले माल
13.	माल, जिसके लिए ड्यूटी क्रेडिट का दावा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात बिल में दर्ज नहीं किया गया है
14.	माल जो विनिर्माण के बाद उपयोग में लिया गया है अथवा पुनर्निर्मित/ उन्नत किए गए/ पहने गए/ उपयोग में लाए गए कपड़े।

[फा. सं. 605/10/2022-प्रतिअदायगी]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2023

**No. 25/2023-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 262(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the manner of issue of duty credit for goods exported under the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (hereinafter referred to as the Scheme), subject to such conditions and restrictions as specified herein, in accordance with Government of India, Ministry of Textiles' notification No. 12015/11/2020-TTP dated the 13<sup>th</sup> August, 2021.

**2.** Such duty credit shall be subject to the following conditions, namely:-

(1) that the duty credit is issued -

(a) against exports of garments and made-ups (hereinafter referred to as the said goods) and their respective rate and cap as listed in Schedules 1, 2, 3 and 4 to the notification of Government of India, Ministry of Textiles' notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II), dated the 8th March, 2019 for the Scheme:

Provided that the value of the said goods for calculation of duty credit to be allowed under the Scheme shall be the declared export Free on Board (FoB) value of the said goods or up to 1.5 times the market price of the said goods, whichever is less;

(b) against claim of duty credit under the Scheme made by an exporter by providing the appropriate declaration at the item level in the shipping bill or bill of export in the customs automated system;

(c) against the shipping bill or bill of export, presented under section 50 of the said Act where the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act has been made;

(d) after the claim is allowed by Customs upon necessary checks, including on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria, and after filing of export manifest or export report;

(e) in accordance with any rules or regulations issued in relation to duty credit, e-scrip or electronic duty credit ledger;

(2) that such duty credit shall be used for payment of the duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) on goods when imported into India;

(3) that the export categories or sectors listed in Table annexed hereto shall not be eligible for duty credit under the Scheme;

(4) that the duty credit allowed under the Scheme, against export of goods notified *vide* notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II), dated the 8<sup>th</sup> March, 2019 for the Scheme, shall be subject to realisation of sale proceeds in respect of such goods in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), failing which such duty credit shall be deemed to be ineligible;

(5) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations which allow the bill of entry and shipping bill or bill of export to be presented and processed electronically on the customs automated system;

(6) that the exporter has realised the sale proceeds against export of goods made earlier by the said exporter where the period allowed for realisation, including any extension of the said period by the Reserve Bank of India, has expired:

Provided that duty credit shall be issued by Customs in excess of the ineligible amount of duty credit pertaining to the unrealised portion of sale proceeds against export of goods made earlier:

Provided further that if the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs has reason to believe, on the basis of risk evaluation or on the basis of enquiry, that the claim of duty credit made by an exporter on export goods may not be bona fide, he may direct, for reasons to be recorded in writing, to allow duty credit after realisation of sale proceeds of such exports;

(7) that duty credit under the Scheme for exports made to Nepal, Bhutan and Myanmar shall be allowed only upon realisation of sale proceeds against irrevocable letters of credit in freely convertible currency established by importers in Nepal, Bhutan and Myanmar in favour of Indian exporters for the value of such goods.

**3. Cancellation of duty credit.**- (1) Where a person contravenes any of the provisions of the said Act or any other law for the time being in force or the rules or regulations made thereunder in relation to exports to which the duty credit relates, or in relation to the e-scrip, the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs having jurisdiction over the customs station of registration of the e-scrip may, after enquiry, pass an order to cancel the said duty credit or e-scrip.

(2) Where the e-scrip is so cancelled, the duty credit amount in the said e-scrip shall be deemed never to have been allowed and the proper officer of Customs shall proceed to recover the duty credit amount used in such e-scrip or transferred from such e-scrip.

(3) The proper officer of Customs may, without prejudice to any other action that may be taken under the said Act or any other law for the time being in force, suspend the operation of the said e-scrip or the electronic duty credit ledger of such exporter or any duty credit transferred from such e-scrip, during pendency of the enquiry under sub-para (1).

**4. Recovery of amount of duty credit.-** (1) Where an amount of duty credit has, for any reason, been allowed in excess of what the exporter is entitled to, the exporter shall repay the amount so allowed in excess, himself or on demand by the proper officer, along with interest, at the rate as fixed under section 28AA of the said Act for the purposes of that section, on that portion of duty credit allowed in excess, which has been used or transferred, and where the exporter fails to repay the amount along with interest, as applicable, it shall be recovered in the manner provided in section 142 of the said Act.

**5. Recovery of amount of duty credit where export proceeds are not realised.-** (1) Where an amount of duty credit has been allowed to an exporter but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised by the exporter in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the exporter shall, himself or on demand by the proper officer, repay the amount of duty credit, along with interest, at the rate as fixed under section 28AA of the said Act for the purposes of that section, within fifteen days of expiry of the said period.

(2) In case any extension of the said period for realisation of sale proceeds has been given by the Reserve Bank of India and the exporter produces evidence of such extension to the proper officer, and if the said sale proceeds are not realised in such extended period, the exporter shall repay the said amount of duty credit along with the said interest, within fifteen days of expiry of the said period.

(3) If a part of the sale proceeds has been realised, the amount of duty credit to be recovered shall be the amount equal to that portion of the amount of duty credit allowed which bears the same proportion as the portion of the sale proceeds not realised bears to the total amount of sale proceeds.

(4) Where the exporter fails to repay the duty credit amount within the said period of fifteen days, the said duty credit shall be deemed never to have been allowed and it shall be recovered, along with the said interest, in the manner as provided in section 142 of the said Act.

**6.** During the pendency of any recovery, as provided in paras 4 and 5, no further duty credit, on any subsequent exports, shall be allowed to such exporter till the time such recovery is made and any unutilised duty credit with the exporter shall be suspended pending such recovery.

*Explanation –* For the purposes of this notification, -

(a) “claim” means a claim of duty credit under the Scheme made by an exporter in the shipping bill or bill of export by providing the appropriate declaration at the item level in the said shipping bill or bill of export in the customs automated system;

(b) “duty credit” means the amount of credit of duty allowed by Customs against a claim under the Scheme;

(c) “electronic duty credit ledger” means the ledger in the customs automated system relating to a person who is the recipient of duty credit or to person to whom the duty credit is transferred;

(d) “e-scrip” means the scrip, created in the ledger for duty credit, as mentioned in *Explanation 1* of section 28AAA of the said Act;

(e) “export manifest” or “export report” means the reference to the terms used in section 41 of the said Act;

(f) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No. 01/2023, dated the 31st March, 2023;

(g) “garments and made-ups” shall have the same meaning as assigned to them in the Government of India, Ministry of Textiles’ notification No. 12015/11/2020-TTP, dated the 13<sup>th</sup> August, 2021 notifying the continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL);

(h) “proper officer” means Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs.

TABLE

Sl. No.	Export categories or sectors ineligible for duty credit
(1)	(2)
1.	Goods which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC-HS
2.	Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of Foreign Trade Policy
3.	Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country but trans-shipped through India
4.	Goods subject to minimum export price or export duty
5.	Deemed exports under Foreign Trade Policy
6.	Goods manufactured or exported by any of the units situated in Special Economic Zone/ Free Trade Warehousing Zone/ Export Processing Zone
7.	Goods manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent Export Oriented Unit
8.	Goods exported under Advance Authorisation or Duty Free Import Authorisation issued under the relevant Foreign Trade Policy:  Provided that where exports are made against Special Advance Authorisation issued under paragraph 4.04A of the Foreign Trade Policy, 2023 in discharge of export obligations in terms of notification No. 27/2023-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> April, 2023, the rates of the RoSCTL Scheme specified in Schedules 3 and 4 to the Ministry of Textiles' notification No. 14/26/2016-IT, dated the 8th March, 2019 shall apply.
9.	Goods manufactured and supplied by units in Domestic Tariff Area to units in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone
10.	Goods manufactured in Special Economic Zone/ Free Trade Warehousing Zone/ Export Oriented Unit/ Export Processing Zone and exported through DTA unit
11.	Goods manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)
12.	Goods availing the benefit of the notification No. 32/1997-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> April, 1997
13.	Goods for which claim of any duty credit is not filed in a shipping bill or bill of export in the customs automated system
14.	Goods that have been taken into use after manufacture or reconditioned/ upgraded/ worn/ used clothes.

[F. No. 605/10/2022-DBK]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.